नई सोच एक्सप्रेस

हर खबर पर पैनी नजर

(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

पेज : 12

क्राइस्टचर्च टेस्ट-लंच के बाद सही लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करने का मिला फायदा...



www.naisochlive.com | पटना, शनिवार, 28 नवंबर 2026, वर्ष- 09, अंक- 271, पृष्ठ-12, मूल्य - 3:00 | naisochexpress@gmail.com

कैबिनेट बैठक के बाद परिसीमन संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर, 25 साल संख्या नहीं बदलेगी

30 नवंबर को लोकसभा, 2 दिसंबर को राज्यसभा में बिल आएगा



एजेंसी। नई दिल्ली

शुक्रवार दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। अब इन कयासों पर अर्ध मोहर लग चुकी है। परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि ये बैठक 45 मिनट तक चली। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में परिसीमन विधेयक को मंजूरी मिली। अब सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी। अब इस विधेयक के आने के बाद महिला आरक्षण कानून में बदलाव होगा। परिसीमन विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 सीटें करने और 2029 के चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है।

दूसरी बार परिसीमन विधेयक को विपक्ष का मिला समर्थन : इससे पहले अप्रैल में ये विधेयक लोकसभा में तय बहुमत नहीं मिलने की वजह से पारित नहीं हो पाया था। अब बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के सामने संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती है।

महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू : बता दें कि परिसीमन विधेयक को यदि लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाता है तो महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। फिलहाल इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान है, जबकि 2051 तक सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखा जाएगा। बता दें कि ये निर्णय संसद के स्पेशल सेशन के लिए फिर से शुरू होने से कुछ दिन पहले आया है क्योंकि सरकार अप्रैल में बिल के हारने के बाद इसे पास करने की एक और कोशिश करने की तैयारी कर रही है।

महिला रिजर्वेशन से जुड़ा संशोधन बिल भी मंजूर : जानकारी के मुताबिक, मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद परिसीमन बिल को मंजूरी भी मिली है और रिजर्वेशन से जुड़ा संशोधन भी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। परिसीमन बिल को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नई पारी खेल चुकी है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। अब 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही प्रस्तावित है। वहीं 3 दिसंबर को सत्रावसान होगा।

इंडिया गठबंधन में फूट, राजद सांसद ने किया परिसीमन बिल का समर्थन; सुप्रिया ने बनाई दूरी

नई दिल्ली। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। सरकार इस दौरान विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। इस बार सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2051 तक राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने अप्रैल 2026 में भी परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं जुटा सका था। अब करीब सात महीने बाद सरकार संशोधित प्रस्ताव के साथ फिर संसद में जाने की तैयारी में है।

हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी



एजेंसी। नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना सभी सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) को अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करने और एक समावेशी क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। जयशंकर ने यहां आईओआरए की 25वीं मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिहाज से केंद्रीय महत्व रखता है। यह क्षेत्र अपार विविधता, अवसरों और साझा चुनौतियों से भरा है। ऐसे में सभी देशों की जिम्मेदारी है कि इसे शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के साथ विकास के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आईओआरए के प्रति भारत का दृष्टिकोण और संगठन की अध्यक्षता विजन महासागर (महासागर) से निर्देशित है। इसका आशय विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति सुनिश्चित करना है। यह भारत के पहले के सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में 'नवाचार, खुलापन, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता' है। ये सिद्धांत इस विश्वास को दर्शाते हैं कि आईओआरए को बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण के प्रति संवेदनशील और अनुकूल बने रहना चाहिए तथा अपने सदस्य देशों को ठोस लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान आईओआरए के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने, संवाद साझेदारों के साथ भागीदारी गहरी करने, व्यावहारिक क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देने तथा संगठन की वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र में आईओआरए की व्यापक भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उसकी संस्थागत नींव मजबूत करना आवश्यक है। इस संदर्भ में बैठक का विषय 'मजबूत क्षेत्रीय आवाज : बदलती वैश्विक व्यवस्था में आईओआरए की स्थिति' विशेष रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलावों के दौर में आईओआरए को अपनी सामूहिक आवाज बुलंद करने और एक समावेशी क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय, संवाद साझेदारों के साथ सार्थक सहयोग और व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि बैठक में होने वाला विचार-विमर्श इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मददगार होगा और आईओआरए के भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा तय करेगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से रचनात्मक चर्चा और अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आह्वान किया।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में कुदरत का कहर! तूफान और बाढ़ से बिगड़े हालात, लाखों घरों की बिजली गुल



वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे के अवसर पर आए भीषण तूफान ने पूर्वी तट और मिडवेस्ट के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खराब मौसम के कारण न्यूयॉर्क की मशहूर मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को भी शनिवार तक के लिए टालना पड़ा। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'पावरआउटेज डॉट यूएस' के अनुसार, गुरुवार शाम तक अमेरिका के मिडवेस्ट और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नौ लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल रही। इनमें पेंसिल्वेनिया के दो लाख से अधिक उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं, वर्जीनिया और मिसौरी में भी एक-एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के मुताबिक, गुरुवार शाम तक अमेरिका आने-जाने वाली दो हजार से अधिक उड़ानें देरी से चल रही थीं, जबकि 420 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान के कारण पूर्वी तट के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में ईडी का आठ ठिकानों पर छापा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू कार्यालय ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आठ ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के कठुआ और उधमपुर तथा पंजाब के पठानकोट सहित अन्य स्थानों पर की जा रही है। मामले में पूर्व सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कर्मी गुरमीत सिंह और उसके सहयोगियों पर अधिक और निश्चित मासिक रिटर्न का झांसा देकर लोगों से निवेश कराने का आरोप है। ईडी के अनुसार, यह जांच जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार की विभिन्न पुलिस एजेंसियों की ओर से दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई है। इन मामलों में आम लोगों के साथ-साथ सेवारत और सेवानिवृत्त एसएसबी कर्मियों से कथित तौर पर धोखाधड़ी किए जाने के आरोप हैं। आरोपितों ने निवेशकों को अधिक और सुनिश्चित मासिक लाभ का भरोसा देकर रकम जमा कराई थी। जांच के दौरान वित्तीय आंकड़ों की पड़ताल में सामने आया कि आरोपितों ने विभिन्न कंपनियों और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए। इनमें कठुआ स्थित मेसर्स स्टाइल ओ इंडस्ट्री, मेसर्स स्टाइल ओ कम्फर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। ईडी के मुताबिक, इन संस्थाओं का संचालन और नियंत्रण आरोपितों के पास था। ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आज तलाशी अभियान शुरू किया है।

किरेन रिजिजू ने चार दिवसीय संसद सत्र में सदस्यों से सार्थक चर्चा का आग्रह किया



नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों से सोमवार से शुरू होने वाले चार दिवसीय संसद सत्र में सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया है। किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों को 2 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्यसभा के सत्र में भी पेश किया जाएगा। लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर को फिर से शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की बैठकें 2 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सोमवार से शुरू होने वाले लोकसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पेश करेगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कहा, "मैंने पहले ही ऐसी टिप्पणियां न करने की अपील की है। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में कई सत्र होते हैं मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र और जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं। संसद के भीतर सदस्य अपने विचार खुलकर रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से काम करे। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है और इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की है। रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और संसद के प्रत्येक सदस्य से यह भी आग्रह किया कि वे पेश किए जाने वाले विधेयकों पर होने वाली चर्चा में पूरे मन से हिस्सा लें।

आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा को संरक्षित और विकसित करने में केरलम का महत्वपूर्ण योगदान : राष्ट्रपति

एजेंसी। त्रिशूर (केरलम)



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि आयुर्वेद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ उसकी शास्त्रीय शिक्षा और चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध परंपरा को संरक्षित एवं आगे बढ़ाने में केरलम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां वैद्य परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही चिकित्सा संबंधी ज्ञान-परंपरा को भी समृद्ध किया गया है। प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की परंपराएं आज भी निरंतर विकसित हो रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मु शुक्रवार को केरलम के त्रिशूर में वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका प्रामाणिक साहित्य केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रहा है। केरलम में मलयालम और मणिप्रवालम भाषाओं में भी अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई तथा उन पर टीकाएं लिखी गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक आयुर्वेद महाविद्यालय का दायित्व है कि वह प्रामाणिक और प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करे। साथ ही, वहां समकालीन परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आयुर्वेद की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे संस्थानों को ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने चाहिए, जिनमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की समझ और दूरदृष्टि हो। उन्होंने वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय की कार्य-संस्कृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संस्थान इसी आदर्श के अनुरूप कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय जैसे संस्थान वर्ष 2047 तक स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केरलम की आयुर्वेदिक परंपरा की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यहां आयुर्वेद की व्यावसायिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ परोपकार और समाजसेवा की भावना भी जुड़ी हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करते समय इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। उन्हें यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि पारंपरिक ज्ञान पर आधारित उद्यमशीलता को किस प्रकार वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा के साथ जोड़ा जा सकता है।

संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा



नई दिल्ली। संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इससे लोकसभा में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का अंतर बढ़ सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) ने अपने सभी सांसदों को विशेष सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विनिर्माण क्षेत्र को गति देने में विफल मोदी सरकार अब लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का कृत्रिम रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी। रमेश ने पार्टी की तीन मांगें दोहराईं।

भारत ने अपना 60 टन से अधिक सोना ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से वापस मंगाया



नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाकर अपने सोने के भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से वापस देश में मंगा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 60 टन से अधिक सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंकों से वापस भारत मंगाया है। इस पहल के बाद, भारत के कुल सोने के भंडार का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा अब देश की ही तिजोरियों में सुरक्षित है, जो लगभग 740 टन के बराबर है। पहले भारत के सोने का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में रखा जाता था, लेकिन अब केवल थोड़ी मात्रा ही यूरोप में बची है। इस कदम को वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय रूस के 2022 के अनुभव से प्रेरित है, जब यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के केंद्रीय बैंक की लगभग 300 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज किया था। हालांकि, रूस ने युद्ध से काफी पहले ही समझदारी दिखाकर अपना अधिकांश भौतिक सोना विदेशी बैंकों से निकालकर देश की तिजोरियों में सुरक्षित कर लिया था।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास गाथा मजबूत और भरोसेमंद : गोयल

एजेंसी। नई दिल्ली



केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास गाथा मजबूत, लचीली और भरोसेमंद बनी हुई है। दुनिया का भारत पर लगातार विश्वास बढ़ा है और देश ने अपने आर्थिक प्रदर्शन से इस भरोसे को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दो से तीन दशकों में दुनिया के पसंदीदा व्यापारिक साझेदार, आकर्षक निवेश केंद्र और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। श्री गोयल शुक्रवार को आयोजित भारत ऋण पूंजी बाजार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश की आर्थिक उपलब्धियों, निरंतर जारी सुधारों, बढ़ते व्यापारिक अवसरों और भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ऋण बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से विचार रखे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है और दूसरी तिमाही में भी विकास की गति कायम रहने की उम्मीद है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में भारत का निर्यात 570 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। देश इस वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 19 प्रतिशत की ऋण वृद्धि भी अर्थव्यवस्था और ऋण बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने दो जारी युद्धों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आयात शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं, वैश्विक व्यापारिक अवसरों में बदलाव, समुद्री मार्गों में व्यवधान और हवाई यात्रा को प्रभावित करने वाली घटनाओं जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इसके बावजूद देश की आर्थिक विकास यात्रा प्रभावित नहीं हुई है।

कैंसर के इलाज और शोध को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास जरूरी : उपराष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली



उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कैंसर के उपचार और इससे जुड़े शोध को बेहतर बनाने के लिए देशभर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के बीच सामूहिक प्रयासों तथा सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अनुसंधान और नई खोजों का लाभ पूरी मानवता तक पहुंचना चाहिए, न कि इसे कुछ देशों या विशेष वर्गों तक सीमित रखा जाना चाहिए। राधाकृष्णन ने यहां ओखला स्थित होली फैमिली अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने 'होली फैमिली अस्पताल स्मारिका 2026' का विमोचन किया और नए ब्लॉक के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए देशभर के कैंसर अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न संस्थान अपने शोध, अनुभव, ज्ञान और उपचार के बेहतर तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। उन्होंने इस दिशा में सहयोग को मजबूत करने के लिए पहल की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ करुणामय, मानवीय और किफायती उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से विशेष चिकित्सा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी लेकिन ऐसी सुविधाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्नत उपचार कितनी किफायती दरों पर और कितनी मानवीय संवेदना के साथ उपलब्ध कराया जाता है। राधाकृष्णन ने कहा कि किसी अस्पताल की वास्तविक शक्ति केवल उसके बुनियादी ढांचे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से नहीं बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण, विशेषज्ञता तथा मानवीय संवेदना से तय होती है। होली फैमिली अस्पताल की विरासत का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी।

गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई: एके-47 और 23 कारतूस के साथ आतंकी गिरफ्तार

वडोदरा। गुजरात में आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने वडोदरा के पास जरोद बस स्टैंड से असम निवासी मोहम्मद शाहरुख इस्लाम को एके-47 राइफल और 23 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में उसके पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की बात सामने आई है। एटीएस की जांच के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब एक साल से जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन की तलाशी में संगठन से जुड़ी संदिग्ध सामग्री भी मिली है। एजेंसी पिछले छह महीने से अधिक समय से उस पर नजर रख रही थी। पुख्ता सूचना मिलने के बाद जरोद बस स्टैंड पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर गुजरात के सार्वजनिक स्थानों पर आतंकी हमला करने के इरादे से राज्य पहुंचा था। वह असम से ट्रेन और बस के जरिए गुजरात आया था। वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास भी उसके ठहरने की जानकारी मिली है। एटीएस के अनुसार, आरोपी के पास से बरामद एके-47 राइफल वह पड़ोसी राज्य से लेकर आया था।

केजरीवाल का 'शीश महल' खुला, महंगे फर्नीचर कीमत के साथ प्रदर्शित

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास 'शीश महल' को शुक्रवार को मीडिया के लिए खोला है। 'शीश महल' में रखे महंगे फर्नीचर को उनकी कीमत के साथ प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक बयान जारी करते हुए 'शीश महल' को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता के बाद अब पंजाब की जनता को भी देखना चाहिए कि किस तरह जनता की खून-पसीने की कमाई से आलीशान शीशमहल बनाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता के सामने इस पूरे मामले की सच्चाई आनी चाहिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली की जनता का पैसा, यानी टैक्स देने वालों का पैसा कहां और कितना खर्च किया गया, इसका पूरा हिसाब हर सरकार को देना चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि दिल्ली के विकास पर खर्च होने वाला उसका पैसा पिछले मुख्यमंत्री ने किस तरह का फर्नीचर खरीदने में खर्च किया। यहां हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बना उद्यमिता का नया केंद्र : उमेश

पटना।जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था एक्सिस कैपिटल की हालिया आर्थिक रिपोर्ट पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में सक्रिय कंपनियों की बढ़ती संख्या राज्य की बदलती आर्थिक तस्वीर और उद्यमिता के विस्तार का परिचायक है। यह विकासपुरुष नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन और विकासोन्मुख नीतियों का प्रतिफल है। उनके नेतृत्व में बिहार ने आधारभूत संरचना, निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। श्री कुशवाहा ने कहा कि एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 से 2026 के बीच बिहार में सक्रिय कंपनियों की संख्या में 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। जून 2026 तक राज्य में सक्रिय कंपनियों की संख्या बढ़कर 58,117 हो गई है। यह आंकड़ा बिहार की बदलती आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ते कारोबारी विश्वास और उद्यमिता के विस्तार का महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। इन सकारात्मक बदलावों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है और राज्य में व्यवसाय एवं उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को नई गति दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि बिहार में निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी पहल की गई हैं। राज्य की स्टार्टअप नीति, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और सिंगल विंडो क्लीयरेंस जैसी व्यवस्थाओं ने छोटे-बड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परिसीमन से दलित, वंचित समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मिलेगा नया अवसर : सुमन

पटना। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लघु जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार डॉ. संतोष कुमार सुमन ने परिसीमन का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बदलती जनसंख्या और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। परिसीमन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे दलित, वंचित समाज के कमजोर वर्गों की राजनीतिक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व को और मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। विशेषकर दलित समाज के लिए यह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक आधार लोकहित और आम जनता की भागीदारी है। भारत एक राष्ट्र के रूप में काम करता है, न कि अलग-अलग राज्यों में विखंडित होकर। जनसंख्या, क्षेत्रीय संतुलन और राज्यों के हित महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके नाम पर परिसीमन की मूल भावना को बाधित करना उचित नहीं है। राज्यवार या भाषावार असंतुलन की आशंकाओं का समाधान संवाद और संवैधानिक व्यवस्था से होना चाहिए।डॉ. सुमन ने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वालों को विशेष रूप से दलित और वंचित समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर वर्ग को लोकतंत्र में उचित भागीदारी और अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर मिले। परिसीमन को राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और करोड़ों देशवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों के नजरिये से देखने की जरूरत है।

दीक्षा पोर्टल की शैक्षिक सामग्री की समीक्षा के लिए बनी समिति

पटना। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री की समीक्षा और गुणवत्ता सुधार के लिए 16 सदस्यीय समिति गठित की गई है। एससीईआरटी के निदेशक यतेन्द्र कुमार पाल ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।समिति की अध्यक्षता एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डायट डॉ. सुरेंद्र कुमार करेंगे। दूरस्थ शिक्षा विभाग के प्रभारी डॉ. राम विनय पासवान को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।समिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के नामित सदस्यों के अलावा एससीईआरटी के संजय कुमार, अजय कुमार शुक्ला और डॉ. गणेश प्रसाद साव शामिल हैं। वहीं, डायट विक्रम के डॉ. रितेश कुमार, सीटीई सारण के डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डायट भागलपुर की ांचला कुमारी और डायट सोनपुर की अभिलाषा कुमारी सदस्य होंगी। विद्यालय स्तर से समस्तीपुर के प्रधानाध्यापक सौरभ कुमार और सारण के सहायक शिक्षक नसीम अख्तर को शामिल किया गया है। मंत्रा सोशल सर्विसेज के निशांत कुमार, राजीव रंजन और आदर्श गुप्ता भी समिति के सदस्य होंगे। समिति दीक्षा पोर्टल पर बिहार टेनेंट की सभी शैक्षिक सामग्रियों की समीक्षा करेगी। इसमें कोविड काल में विकसित सामग्री भी शामिल है। पाठ्यक्रम से सामग्री का मिलान, गलत टैगिंग एवं मैपिंग में सुधार और क्यूआर कोड की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। हर सामग्री को रखने, हटाने या संशोधित करने का निर्णय भी समिति लेगी। इसके बाद सामग्री की कमियों का अभिलेखन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समिति को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों ने संकेतों से संवाद करना सीखा

पटना। श्रवणबाधित छात्राओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से महेन्द्रू स्थित एससीईआरटी में पांच दिनों से जारी कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। समावेशी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला का विषय 'संकेत से समावेशन' था। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों को भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया गया। 23 दिसम्बर से शुरू हुई कार्यशाला का समापन डायट के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार और समावेशी शिक्षा विभाग के प्रभारी विजय कुमार भास्कर की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में हुआ। कार्यशाला में शिक्षकों को भारतीय सांकेतिक भाषा के बुनियादी कौशल सिखाए गए। उन्हें श्रवणबाधित छात्राओं से प्रभावी संवाद करने के तरीके बताए गए। साथ ही, कक्षाओं में समावेशी शिक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।सहभागितापूर्ण गतिविधियों, व्यावहारिक अभ्यासों और प्रदर्शन आधारित सत्रों में शिक्षकों ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करना सीखा। उन्हें बताया गया कि संवाद ही समावेशन की आधारशिला है। हर बच्चे को अपनी बात कहने, समझे जाने और सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस पहल से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में श्रवणबाधित छात्राओं के लिए अधिक सहज और समावेशी शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

बिहार में 2030-31 तक बनकर तैयार हो जाएंगे 2 नए एयरपोर्ट : सचिव

नई सोच एक्सप्रेस



पटना।बिहार में हवाई संपर्क को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार सजग है। वर्ष 2030-31 तक दो नए ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट का निर्माण करा लिया जाएगा। इसमें सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर क्षेत्र में मौजूद अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आगामी 3 से 4 वर्षों में राज्य के पांच प्रमुख हवाई अड्डों पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया और रक्सौल भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बातें सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश तथा मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में कई स्थानों से लोगों को बेहतर हवाई सुविधा के विकल्प मिलने लगेंगे। **दरभंगा में जल्द तैयार होगा नया टर्मिनल और रनवे:**सचिव ने बताया कि पटना टर्मिनल के अपग्रेडेशन का काम पूरा हो चुका है। वहीं, दरभंगा में नये टर्मिनल और रनवे का काम तेजी से चल रहा है। यहां करीब 3700 मीटर लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है। नये टर्मिनल का काम वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में मान्यता के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। यहां कार्गो हब के लिए जमीन एक्वायर किया जा रहा है। भू-अर्जन का काम 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। **पूर्णिया में बनेगा कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एयरोसिटी:**श्री देवरे ने कहा कि पूर्णिया में भी रवने को अपग्रेड करने का काम जारी है। पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास एवं संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से भारतीय विमानपतन प्राधिकरण(एएआई) को 67.18 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है। प्राधिकरण की ओर से यहां 294.05 करोड़ सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हवाई अड्डा के पास कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एयरोसिटी के निर्माण के लिए करीब 567 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के लिए लगभग 290 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। **गया एयरपोर्ट पर घने कोहरे में भी उतर सकेंगे विमान:**सचिव ने कहा कि गया एयरपोर्ट पर कैट-1 लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके स्थापित होने के बाद घने कोहरे, धुंध और कम विजिबिलिटी के दौरान भी यहां विमानों की सुरक्षित लैडिंग हो सकेगी। इसके साथ ही गया कम विजिबिलिटी में भी विमानों का संचालन करने वाला बिहार का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। **रक्सौल एयरपोर्ट के तैयार की जा रही डीपीआर:**रामचंद्र देवरे ने कहा कि मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, वीरपुर और सहरसा के हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। रक्सौल में बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित इस बड़े एयरपोर्ट को 3-4 साल में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 139 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) को जमीन सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। वहीं, मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर करीब 27.67 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन और 31.20 करोड़ रुपये से रनवे का निर्माण शुरू हो चुका है। जबकि वाल्मीकिनगर में 27.15 करोड़ रुपये से टर्मिनल और 23.80 करोड़ रुपये से रनवे बनाया जाएगा। यहां संपर्क सड़क के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि वीरपुर में 88.83 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है। यहां 30.48 करोड़ रुपये से टर्मिनल भवन और 28.42 करोड़ रुपये से रनवे बनेगा। सहरसा में भी रनवे के अतिरिक्त विकास के लिए 12 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यहां रनवे निर्माण पर 42.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जनता का सभी काम पंचायत सरकार भवन में होगा ब्लॉक जाने की जरूरत नही:- मंत्री श्रवण कुमार

नई सोच एक्सप्रेस



बिहारशरीफ।नूरसराय प्रखण्ड के मुज्जफरपुर पंचायत में शुक्रवार को दो करोड़ 98 लाख की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का शुभ गृह प्रवेश बिहार सरकार के ग्रामीण विकास व सूचना जनसम्पर्क मंत्री श्रवण कुमार व विधान पार्षद व सचेतक रीना यादव व जदयू के वरिष्ट नेता राजेन्द्र प्रसाद ने फीता काट कर किया इस अवसर पर मंत्री श्री कुमार ने कहा कि अब पंचायत की आम जनता को प्रखण्ड का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नही है सभी कार्य पंचायत सरकार भवन में ही होगा पेंशन जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र सब यही बनेगा इसमें मुखिया जी पंचायत सेवक सरपंच साहेब पंचायत समिति सदस्य वार्ड सदस्य सब यही मिलेगा आम जनता को सहूलियत होगा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे हम लोग जनता की कार्य से लिये सदैव तैयार रहते है इस अवसर पर विधानपार्षद सदस्य रीना यादव ने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास कार्य हो रहा है जो बिहार में विकास का कार्य हुआ है उसका अनुकरण दूसरे राज्य ने हो रहा है सूबे में सड़कों का जाल बिछ रहा है वही इन अवसर पर जदयू के वरिष्ट नेता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है न्याय के साथ विकास कार्य हो रहा है बिहार के सभी वर्गों का विकास में भागेदारी मिल रही है इस अवसर पर जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष राकेश कुमार बी डी ओ जियाउल हक सी ओ दीपक कुमार राजू कुमार नीरज कुमार डॉ सुनील दत्त बंटी यादव बबलू कुमार रजनीश कुमार शैलेन्द्र गराई सोनू सुल्तान दीपू सिंह कक्कू मुखिया आदि लोग उपस्थित थे।

विधानसभा स्तरीय निर्वाचन साक्षरता का आयोजन, 10 विद्यार्थियों का चयन

नई सोच एक्सप्रेस



दानापुर।जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी दानापुर निर्वाचन क्षेत्र वीरूपाक्ष विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार दानापुर में विधानसभा स्तरीय निर्वाचन साक्षरता क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी एवं भावी कॉलेज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना, उनमें निर्वाचन संबंधी जागरूकता विकसित करना और मतदान का महत्व और अपने मताधिकार के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। कार्यक्रम में वीरूपाक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि ELC केवल एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक उद्देश्य और दूरगामी सोच है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरों और भावी लाइब्रेरी को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना और उनमें मतदान के प्रति जागरूकता विकसित करना है। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के 20 विद्यालयों में गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से पहले स्कूल स्तर पर निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने चुनावी प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में मतदाता सूची की शुद्धता एवं मतदान के महत्व संबंधित प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में 10 छात्र छात्राओं का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस अवसर पर अवर निर्वाचक पदाधिकारी बिरेन्द्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार, शिक्षक विजय शाह, संजीत कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, प्रियंका, काजल आदि शामिल थें।

गोबर और कृषि अपशिष्ट से बनेगी जैविक खाद : विजय

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा किसानों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बिहार राज्य जैविक मिशन के अंतर्गत पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई एवं व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देकर जैविक खाद के उत्पादन और कृषि अपशिष्ट के सदुपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों को अपने खेतों एवं पशुओं से प्राप्त जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक लाभुक को अधिकतम तीन पक्का वर्मी कम्पोस्ट पीट इकाइयों का लाभ दिया जाता है। प्रति पीट 10,000 रुपये की कुल लागत पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5,000 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में कुल 51,000 पक्का वर्मी कम्पोस्ट पीट इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि पशुओं के गोबर एवं अन्य जैविक अपशिष्ट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गोबर/बायोगैस इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक लाभुक को एक इकाई का लाभ दिया जाता है। इकाई की कुल लागत 42,000 रुपये पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 21,000 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त टर्न की राशि के रूप में 1,500 रुपये का सहयोग भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 300 गोबर/बायोगैस इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3,000, 2,000 एवं 1,000 मीट्रिक टन क्षमता की इकाइयों के लिए क्रमशः 50 लाख, 32 लाख एवं 16 लाख रुपये की लागत पर 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम क्रमशः 20 लाख, 12.80 लाख एवं 6.40 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 20 व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि इन योजनाओं के लाभुकों का चयन ऑनलाइन डीबीटी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया जाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि के विजन के अनुरूप हमारा प्रयास है कि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहे, खेतों की सेहत सुधरे और खेती अधिक लाभकारी बने। जैविक खाद के उत्पादन एवं कृषि अपशिष्ट के सदुपयोग से हम उपजाऊ धरती के संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि खेतों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट और पशुओं के गोबर का उपयोग संसाधन के रूप में हो, न कि वह बेकार जाए। इससे किसानों को अपने स्तर पर जैविक खाद तैयार करने का अवसर मिलेगा, खेती की लागत कम होगी और मिट्टी की सेहत में सुधार आएगा। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ने से टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हमारा संकल्प है कि स्वस्थ मिट्टी के आधार पर समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण हो।

जो लोग संविधान को दिखावे के लिए लहराते हैं, वे उसकी स्पिरिट समझें : अमित शाह

नई सोच एक्सप्रेस



पटना।संविधान गौरव दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संविधान के सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और देश के भविष्य को लेकर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। अमित शाह ने कहा कि संविधान को केवल दिखावे के लिए लहराने वालों को उसकी मूल भावना समझनी चाहिए। संविधान की मूल प्रति में भारतीय संस्कृति, महापुरुषों और गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है। संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों तक बैंक खाते, बिजली, शौचालय, पानी, मुफ्त अनाज, स्वास्थ्य सुरक्षा और गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं पहुंची हैं। धारा 370 की समाप्ति, नक्सलवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण तथा पूर्वोत्तर में उग्रवादियों की मुख्यधारा में वापसी संविधान के प्रभावी क्रियान्वयन के उदाहरण हैं। शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के आपातकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौरान मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया था।

आनंद मोहन को राजनीतिक साजिश के तहत फँसा राजपूतों को किया जा रहा अपमानित :अभिजीत सिंह

नई सोच एक्सप्रेस



पटना।सुप्रीम कोर्ट द्वारा आनंद मोहन की जमानत रद्द किए जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को क्षत्रिय महासभा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महासभा के अभिजीत सिंह ने बिहार सरकार पर आनंद मोहन को राजनीतिक साजिश के तहत फँसाने का आरोप लगाया।अभिजीत सिंह ने कहा कि आनंद मोहन के मामले में बिहार सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के साथ न्याय होना चाहिए और इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरती जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि क्षत्रिय महासभा इस प्रकरण को लेकर गंभीर है और आनंद मोहन के साथ खड़ी है। महासभा उनके अधिकारों और न्याय की लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएगी।हम लोग भाजपा जदयू की सरकार के खिलाफ गांव गांव जाएँगे और इस सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे .प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजीव सिंह ने कहा कि बिहार सरकार राजपूत समाज को अपमानित कर रही है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सवर्ण समाज के लोग भाजपा का विरोध करेंगे .एन डी ए का क्षत्रिय समाज विरोध करेगा।

13 जिलों से दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू, 18 मार्गों पर होगा परिचालन

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में अंतरराज्यीय परिवहन को और मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के 13 जिलों से देश की राजधानी दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू हो गई है। ये बसें बिहार के 18 मार्गों से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को संयुक्त रुप से हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम नई दिल्ली के महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर आयोजित हुआ। इसके पूर्व दोनों राज्यों के परिवहन सचिव (बिहार परिवहन सचिव राज कामार एवं दिल्ली परिवहन सचिव निहारिका राय) ने बस परिचालन के लिए एमओयू साइन किया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अनुसार, अंतरराज्यीय मार्गों पर परिचालन के लिए कुल 149 डीलक्स बसें खरीदी गई हैं। इनमें 75 नॉन-एसी एवं 74 एसी बसें हैं। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड में भी 150 बसें चलेंगी। इसके लिए प्रदेश में कुल 18 मार्गों का चयन किया गया है। पटना से सबसे अधिक 4 मार्ग, मुजफ्फरपुर और गया जी से 2-2 मार्ग, जबकि अररिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, नवादा और पूर्णिया से 1-1 मार्ग दिल्ली के लिए चिन्हित किए गए हैं। हर मार्ग पर दिल्ली और बिहार दोनों तरफ से 12-12 परमिट का कोटा निर्धारित है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि पहले यह सेवा केवल पर्व-त्योहारों तक ही सीमित रहती थी। वर्ष 2025 में पर्व-त्योहारों के दौरान ट्रेनों और दूसरे परिवहन साधनों में भारी भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 210 निगम एवं पीपीपी बसें चलाई थीं। इसी क्रम में वर्ष 2026 में दीपावली और छठ पर्व पर बिहार से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न मार्गों पर कुल 155 बसें चलाई गईं। यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया और बढ़ती माँग के बाद यह जरूरी समझा गया कि ये सेवाएं पूरे वर्ष चलें। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार संबंधित राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौते कर रही है।उन्होंने बताया कि इससे पूर्व बिहार-हरियाणा के बीच जुलाई में 12 मार्गों पर नियमित बस संचालन के लिए एमओयू हुआ है। इसके तहत 36 बसों का परमिट निगम को प्राप्त हो चुका है। इन मार्गों में अधिकांश बसें दिल्ली होकर हरियाणा के विभिन्न गंतव्यों तक जाएंगी। इससे बिहार-हरियाणा के साथ-साथ बिहार-दिल्ली के यात्रियों को भी परिवहन सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।आयोजित कार्यक्रम में बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, दिल्ली के चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की कार्यकारिणी परिषद की तीसरी बैठक सम्पन्न

पटना। बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन की सत्र 2026-27 के लिए गठित कार्यकारिणी परिषद की तीसरी बैठक शुक्रवार को घूमर रेस्तरां बेली रोड में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने की। बैठक में कुल 56 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में 12 नये इकाईयों की सदस्यता के आवेदन पर कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें सत्र 2026-27 के लिए एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान की। साथ ही कार्यकारिणी परिषद ने माह अक्टूबर 2026 के आय-व्यय ब्योरा का अध्ययन किया तथा स्वीकृत। आज के कार्यकारिणी परिषद के बैठक का आतिथ्य एसोसिएषन के सदस्य राजीव अग्रवाल अपने रेस्तरॉ घूमर, जो राजस्थानी परिवेष एवं भोजन उपलब्ध कराता है, के द्वारा प्रायोजित किया गया। सदस्यों को परिसर में आगमन पर राजस्थानी परंपरा के अनुरूप तिलक लगाकर तथा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।एसोसिएषन के अध्यक्ष की ओर कार्यकारिणी परिषद की बैठक में दिए जाने वाला प्रषंसा पुरस्कार की कड़ी में नवम्बर माह प्रषंसा पुरस्कार आज की बैठक में अपने सदस्य सीए दीपक कुमार को उनके सक्रिय सहभागिता, उत्कृष्ट सेवा एवं समर्पित सहयोग के प्रति सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया। बैठक का समापन अध्यक्ष राम लाल खेतान द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

पूर्वी जोनल विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता में बिहार को मिला तीसरा स्थान

पटना। कोलकाता स्थित बिड़ला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आयोजित पूर्वी जोनल स्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता में बिहार के प्रतिभागियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दरभंगा प्रमंडल के बीकेडी राजकीय बालक प्लस टू विद्यालय (जिला स्कूल) के छात्र-छात्राओं ने यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से राज्य का गौरव बढ़ा है।विज्ञान एवं समाज विषय पर आधारित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। इसमें बिहार की ओर से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।सफल प्रतिभागियों में राशि कुमारी, बिंदिया कुमारी, सना परवीन, आंचल कुमारी, विकास कुमार शर्मा, अभिनव राजा, साहिल कुमार और ऋषभ कुमार शामिल हैं।इस उपलब्धि पर एससीईआरटी के निदेशक यतेन्द्र कुमार पाल, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राधे रमण प्रसाद और अन्य व्याख्याताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इससे पहले 27 अक्टूबर को एससीईआरटी और श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राज्यस्तरीय विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के प्रतिभागियों ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था।

नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायती राज एवं नगर निकायों में आरक्षण देकर बढ़ाई राजनीतिक भागीदारी : बिजेंद्र

पटना। शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित मामलों के विधिसम्मत एवं समयबद्ध निष्पादन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर जनसुनवाई कार्यक्रम के समन्वय हेतु पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण वर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आधी आबादी को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की।परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस के शासनकाल में भी परिसीमन की प्रक्रिया होती रही है। ऐसे में विपक्ष को इस विषय पर अनावश्यक विरोध से बचना चाहिए।

रोडिक ने 200 करोड़ रुपये का एआई इनोवेशन फंड किया घोषित

पटना। देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनियों में शामिल रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एआई और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन फंड स्थापित करने की घोषणा की है। इस फंड में रोडिक 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि शेष 100 करोड़ रुपये एंजेल फंड्स, वेंचर कैपिटल फर्मों और यूएचएनआईएस के को-इन्वेस्टमेंट से जुटाए जाएंगे। इस पहल के तहत एआई, कंप्यूटर विजन, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोडिक का इंजीनियरिंग अनुभव, इंडस्ट्री नेटवर्क और वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर समाधान आजमाने का अवसर मिलेगा। रोडिक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राज कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य इनोवेशन को प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर ऐसे व्यावहारिक समाधानों में बदलना है, जिन्हें देशभर की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बड़े स्तर पर लागू किया जा सके। इससे परियोजनाओं की योजना, निर्माण, निगरानी, सुरक्षा और संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से रोडिक 22 जनवरी 2027 को भारत मंडपम में रोडिक इंफ्रा-एआई कॉन्क्लेव 2027 का आयोजन करेगा। इसमें नीति-निर्माता, सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, निवेशक, स्टार्टअप्स और शोधकर्ता शामिल होंगे।

नशा मुक्त युवा ही करेगा देश का उत्थान- प्रेम कुमार



पटना। युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान युवाओं के योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित गांधीवादी प्रेम जी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और नशा मुक्त युवा ही करेगा देश का उत्थान। इस अवसर पर *प्रेम यूथ फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की गई। फाउंडेशन के स्वयंसेवक लगातार स्वच्छता, गंगा घाटों की सेवा, छठ महापर्व में सहयोग और समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि आज का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला, समाज बदलने वाला और देश को आगे ले जाने वाला बनेगा। युवाओं को सही दिशा, संस्कार और मौका मिले तो बिहार ही नहीं, पूरा देश आगे बढ़ेगा। फाउंडेशन की ओर से संकल्प लिया गया कि युवा शक्ति को जोड़कर सेवा, शिक्षा और स्वच्छता के लिए काम लगातार जारी रहेगा।

प्रेम और दर्शन के गीतकार थे बच्चन, सरस्वती की साक्षात विग्रह थीं मृदुला सिन्हा

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। प्रेम, उत्साह और दर्शन के महान गीतकार थे हरिवंश राय बच्चन। हिन्दी-काव्य के छायावाद-काल के उत्तरार्ध में एक नवीन और मृदुल-स्पर्श लेकर आए बच्चन जी ने, मनुष्यता को जीवन-रस प्रदान करने वाले 'प्रेम' को नई भाषा दी। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति अकुंठ श्रद्धा और उत्साह है। वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवि थे। वहीं दूसरी ओर गोवा की राज्यपाल रह चुकीं विदुषी डा मृदुला सिन्हा का स्मरण भगवती शारदा की आराधना के समान पावन है। वो सरस्वती की साक्षात विग्रह थीं। उनकी आत्मीयता और सबके प्रति उनका स्नेह-सिक्त व्यवहार उन्हें अतिविशिष्ट बनाता था। देश के महान इतिहासकार डा काशी प्रसाद जायसवाल तो बिहार के गौरव-पुरुष ही थे । वे बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १२वें सत्र के लिए अध्यक्ष भी चुने गए थे। यह बातें शुक्रवार को तीनों महान विभूतियों की जयंती पर साहित्य सम्मेलन में आयोजित समारोह और कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, सम्मेलन अध्यक्ष डा अनिल सुलभ ने कही। उन्होंने कहा कि, बच्चन जी की 'मधुशाला', वस्तुतः दर्शन-काव्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित बच्चन जी राज्य-सभा के भी मनोनीत सदस्य थे। समारोह के मुख्यअतिथि और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्त्ति मान्धाता सिंह ने कहा कि आज जिन साहित्यिक विभूतियों को हम स्मरण कर रहे हैं, वे सभी जन्मजात विशिष्ट गुणों से युक्त थीं। बच्चन जी अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवि और मंचों के आकर्षण थे। उनकी रचनाएँ युवाओं में नूतन उत्साह भरनेवाली हैं। मृदुला जी का व्यक्तित्व बहु-आयामी था। साहित्य, राजनीति और समाजसेवा में उन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया। काशी प्रसाद जायसवाल एक मनीषी विद्वान और इतिहासकार थे। वरिष्ठ साहित्यकार डा रत्नेश्वर सिंह, डा पुष्पा जमुआर, डा नागेश्वर प्रसाद यादव, प्रो सुनील कुमार उपाध्याय और कुमार अनुपम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित कवि-सम्मेलन का आरम्भ चंदा मिश्र की वाणी-वंदना से हुआ। वरिष्ठ कवि सुनील कुमार मलंग, शायरा शमा कौसर 'शमा', प्रो सुनील कुमार उपाध्याय, सदानन्द प्रसाद, चित्तरंजन लाल भारती, राजप्रिया रानी, इन्दुभूषण सहाय, दीपक कुमार बरनवाल आदि कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। मंच का संचालन कवि ब्रह्मानन्द पाण्डेय ने तथा धन्यवाद-ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। डा चंद्रशेखर आज़ाद, राम शंकर शुक्ल, रवि गुप्ता, रूबी झा, स्नेह आनन्द भगत, कुमारी डौली, अर्पित कुमार, भोला प्रसाद, सूरज कुमार, मो फ़हीम, अर्चना भारती आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

मध्यरात्रि में काको मंडल कारा में एसपी की औचक छापेमारी



नई सोच एक्सप्रेस

जहानाबाद (हसनैन दीवाना)। जिले में विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में 26 और 27 नवंबर की मध्यरात्रि को पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में काको स्थित मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल प्रशासन में हलचल मच गई। छापेमारी के दौरान कारागार के सभी वार्डों, सेल और अन्य संवेदनशील स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना, कारागार के अंदर विधि-व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी तरह की अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना था। अधिकारियों ने जेल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच की। साथ ही कारागार की आंतरिक व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इस औचक छापेमारी के दौरान जेल अधीक्षक, उप विकास आयुक्त (डीडीसी), अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं घोषी, घोषी और काको थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने समन्वय के साथ तलाशी अभियान को अंजाम दिया। जहानाबाद पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पावन अवशेषों का बिहार आगमन

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। बिहारवासियों को भारत की प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का विशेष अवसर मिलने जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वावधान में मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पावन अवशेषों के बिहार आगमन के अवसर पर 1 से 11 दिसंबर 2026 तक राज्य के 11 प्रमुख स्थानों पर विशेष दर्शन एवं सामूहिक पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में आर्ट ऑफ लिविंग बिहार की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज्योति सिन्हा ने बताया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है और भारतीय सनातन परंपरा में इसका विशेष महत्व है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, वर्ष 1026 में महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान मूल शिवलिंग खंडित हुआ था। मान्यता है कि अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने इसके पावन अंशों को सुरक्षित रखकर तमिलनाडु में संरक्षित किया। जनवरी 2025 में इस वंश परंपरा के वर्तमान संरक्षकों ने इन अवशेषों को बेंगलुरु में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सौंपा। इन पावन अवशेषों के आध्यात्मिक महत्व पर गुरुदेव ने कहा है, एक हजार वर्षों तक अप्रकट रहने के बाद शिव अब प्रकट हुए हैं। इन पवित्र लिंगों के रूप में उनकी उपस्थिति यह दशार्ती है कि वे अविनाशी हैं। वे शाश्वत हैं। यह आयोजन भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं, सनातन विरासत और सांस्कृतिक चेतना से पुनः जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 2 दिसंबर, बुधवार दोपहर 2:00 बजे बेगूसराय, 3 दिसंबर, गुरुवार सुबह 9:00 बजे पटना सिटी, 5 दिसंबर, शनिवार सुबह 7:00 बजे बक्सर,5 दिसंबर, शनिवार सुबह 10:00 बजे , बक्सर , 6 दिसंबर, रविवार सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान, पटना ,8 दिसंबर, मंगलवार सुबह 9:00 बजे समस्तीपुर , 8 दिसंबर, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे मुजफ्फरपुर, 9 दिसंबर, बुधवार दोपहर 2:00 बजे बांका, 9 दिसंबर, बुधवार शाम 5:00 बजे कहलगांव ,10 दिसंबर, गुरुवार सुबह 10:00 बजे भागलपुर, 1 दिसंबर, शुक्रवार सुबह 10:00 बजे पूर्णिया में जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं को पावन अवशेषों के दर्शन एवं सामूहिक पूजन में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग निरंतर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्था के शिक्षक, स्वयंसेवक एवं विभिन्न जिलों के साधक सक्रिय रूप से सेवा और समन्वय में जुटे हैं। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के एपेक्स रमेंश कुमार, नमिता सिंह,प्रज्ञा अग्रवाल स्वयं प्रकाश, आलोक अग्रवाल, तनु श्री उपस्थित रहे।

11,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना से 'मेक इन इंडिया' को मिलेगी नई ताकत, रोजगार के बढ़ेंगे अवसरः अनिल अग्रवाल

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना लाने के सरकार के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आयात के विकल्प के रूप में देश में ही इन उपकरणों का विनिर्माण करने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। आयात और रोजगार के बीच संबंध को रेखांकित करते हुए अग्रवाल ने कहा, "आयात से दूसरे देशों में रोजगार पैदा होता है, जबकि आयात के स्थान पर देश में ही उत्पादन करने से भारत में रोजगार के अवसर बनते हैं।" उन्होंने कहा कि भारत के पास एक्सकेवेटर, टनल बोरिंग मशीन और क्रेन जैसे उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक क्षमता और इंजीनियरिंग प्रतिभा मौजूद है। पावर उपकरण क्षेत्र से तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का आयात निर्माण उपकरणों के आयात से चार से पांच गुना अधिक है और यह क्षेत्र दोगुनी दर से बढ़ रहा है। अग्रवाल ने BEML, BHEL और HMT जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जो भारी उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण किए जाने पर ये कंपनियां अपने मौजूदा उत्पादन से कम से कम 10 गुना अधिक उत्पादन कर सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार इनका विनिवेश किसी निजी कंपनी को कर सकती है या इनके शेयर व्यापक स्तर पर आम जनता को वितरित कर सकती है, जिससे ये L&T की तरह निजी क्षेत्र की कंपनियों के समकक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हित में उचित समझे जाने वाले तरीके का चयन कर सकती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे की राह बताते हुए अग्रवाल ने तीन समानांतर माध्यमों पर जोर दिया- मौजूदा निजी क्षेत्र, निजीकरण किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषी स्टार्टअप। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रोत्साहन और उत्पादन के इन तीन समानांतर माध्यमों की इसी रणनीति को उन सभी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, जहां भारत की आयात पर निर्भरता 50 प्रतिशत से अधिक है। अपने व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए अग्रवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के युवाओं, महिलाओं और वास्तव में सभी भारतीयों के लिए करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा करना है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 6.59 किलोमीटर लंबी सुरंग-14 के निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण सफलता मिली

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। भारतीय रेल को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की 6.59 किलोमीटर लंबी सुरंग-14 के काम में उल्लेखनीय सफलता मिली। इस उपलब्धि से सुरंग की खुदाई के दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए हैं। इनमें सुमेरपुर की ओर से 4.7 किलोमीटर के पोर्टल-1 और मारोड़ा की ओर से 1.79 किलोमीटर लंबी सुरंग पोर्टल-2 की खुदाई शामिल है। पोर्टल-1 (टी14P1) पर आबादी वाले क्षेत्र के नीचे ढीली मिट्टी से होकर तीन ट्रैक वाली सुरंग के 110 मीटर लंबे हिस्से की खुदाई की गई। इस हिस्से के ऊपर 20 से 30 मीटर तक मिट्टी और चट्टान की परत थी। सुरक्षित खुदाई के लिए खुदाई से पूर्व विशेष उपाय और मल्टी-ड्रिफ्टिंग (इस विधि में पूरी बड़ी सुरंग को एक साथ खोदने के बजाय, पहले उसके अंदर कई छोटे-छोटे क्षैतिज रास्ते खोदे जाते हैं और उन्हें सहारा देने के बाद आपस में जोड़कर पूरी सुरंग का आकार दिया जाता है) सहित विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया गया। पोर्टल-2 (टी14पी2) पर 30 से 35 मीटर गहरे माइक्रोपाइल्स, 15 से 20 मीटर लंबे रॉक बोल्ट और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग द्वारा ढलान को सुरक्षित किया गया। इन उपायों से सुरंग की मुख्य खुदाई का कार्य मार्च 2024 में आरंभ करना संभव हुआ। इससे पहले मारोड़ा में भू-धंसाव की समस्या तथा भूमि और मकानों के अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों का समाधान किया गया। पोर्टल-2 पर लगभग 100 मीटर तक यांत्रिक तरीके से खुदाई की गई। आसपास की बस्तियों की सुरक्षा के लिए दोनों पोर्टल के निकट नियंत्रित विस्फोट का काम केवल दिन के समय और निर्धारित समय अनुसार किया गया। पोर्टल-1 से 4.7 किलोमीटर लंबे खुदाई मार्ग में सुरंग के भीतर ताजी हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने और तापमान नियंत्रित रखने के लिए विशेष वेंटिलेशन प्रणाली भी लगाई गईं। सुरंग-14 के निर्माण कार्य में यह महत्वपूर्ण सफलता ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना निर्माण कार्य में बड़ी उपलब्धि है। यह परियोजना उत्तराखंड में रेल संपर्क बेहतर बनाने के उद्देश्य से आरंभ की गई महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना पहल है। इस परियोजना से पहाड़ी क्षेत्रों तक बेहतर रेल संपर्क स्थापित होगा, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की यात्रा सुगम होगी तथा राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचना आसान होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

बाल विवाह के खिलाफ स्कूलों में चला जागरूकता अभियान, बच्चों को बताए गए कानूनी प्रावधान

नई सोच एक्सप्रेस



जहानाबाद (हसनैन दीवाना)। समाज से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जिले में 100 दिवसीय 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद के तत्वावधान में संचालित इस अभियान के माध्यम से जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जहानाबाद के टेहेटा हाई स्कूल में अधिवक्ता रमेश कुमार की टीम ने विद्यार्थियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अधिवक्ता रमेश कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पेशे से अधिवक्ता हैं और आज विद्यार्थियों के बीच कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने आए हैं, ताकि बच्चे अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों को समझ सकें। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में बाल विवाह की घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन यह कुरीति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसे समाज से जड़ से मिटाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार, विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है और यह कानूनन अपराध है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि कम उम्र में शादी होने से उनकी शिक्षा बाधित होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना तथा परिवार और जिले का नाम रोशन करना है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन या कानून की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

शहरी भारत में दूध रोजाना प्रोटीन का किफायती स्रोत, लैक्टोग्राफ 2.0 रिपोर्ट में खुलासा

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। शहरी भारत में दूध केवल रोजमर्रा के खानपान का हिस्सा ही नहीं, बल्कि प्रोटीन का किफायती और भरोसेमंद स्रोत भी है। गोदरेज जर्सी की लैक्टोग्राफ 2.0 रिपोर्ट के अनुसार, 69 प्रतिशत शहरी उपभोक्ता दूध को दैनिक प्रोटीन का किफायती स्रोत मानते हैं। मुंबई और चेन्नई में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर जारी इस अध्ययन को YouGov ने भारत के आठ शहरों में दूध एवं डेयरी उत्पादों के सेवन की आदतों को लेकर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 60 प्रतिशत लोग रोजाना चाय या कॉफी के जरिए दूध का सेवन करते हैं, जबकि 40 प्रतिशत लोग प्रतिदिन सादा दूध पीते हैं। वहीं, 59 प्रतिशत उपभोक्ता दूध को संपूर्ण प्रोटीन के रूप में पहचानते हैं, जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी नौ अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी लोगों के लिए भी डेयरी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। 86 प्रतिशत शाकाहारी अपने प्रमुख प्रोटीन स्रोतों में डेयरी को शामिल करते हैं, जबकि 65 प्रतिशत दूध को संपूर्ण प्रोटीन मानते हैं। पनीर को 69 प्रतिशत और दही को 47 प्रतिशत लोग संपूर्ण प्रोटीन के रूप में पहचानते हैं। अध्ययन में दूध से जुड़ी पारंपरिक आदतों का भी उल्लेख किया गया है। करीब 10 में से नौ शहरी उपभोक्ता बचपन से जुड़ी डेयरी परंपराओं को आज भी निभाते हैं। इनमें दही-चावल 50 प्रतिशत, गर्मियों में छाछ 49 प्रतिशत, विशेष अवसरों पर बादाम दूध 41 प्रतिशत, सुबह दूध पीना 40 प्रतिशत, रात में दूध पीना 39 प्रतिशत और हल्दी वाला दूध 36 प्रतिशत लोगों की पसंद में शामिल है। गोदरेज जर्सी के सीईओ गौरव पांडे ने कहा कि दूध रोजमर्रा की आदत, पोषण, स्वाद और सुलभता का बेहतर संयोजन है। लैक्टोग्राफ 2.0 उपभोक्ताओं के बीच दूध की पोषण संबंधी समझ को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। रिपोर्ट दूध को दैनिक आहार में किफायती, परिचित और भरोसेमंद प्रोटीन स्रोत के रूप में स्थापित करती है।

संक्षिप्त समाचार

एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में दलसिंहसराय उप-कारा में देर रात छापामारी, हर ब्लॉक और वार्ड की हुई सघन जांच, 2 घंटे तक चली कार्रवाई में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली



समस्तीपुर।पुलिस अधीक्षक ग्रामीण समस्तीपुर के नेतृत्व में 26/27 नवंबर 2026 की रात्रि में उप-कारा दलसिंहसराय में छापामारी की गई। इस छापामारी में अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोसड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दलसिंहसराय, थानाध्यक्ष दलसिंहसराय के अलावा अन्य थानाध्यक्ष समेत वृहत मात्रा में पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। छापामारी के दौरान जेल के प्रत्येक ब्लॉक और उसमें स्थित वार्डों तथा जेल अस्पताल का सघन जांच किया गया। करीब 2 घंटे तक चली इस छापामारी में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है।

बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा के बाद जमुई पहुंचे क्रिकेटर ईशान किशन, डीएम से की आत्मीय मुलाकात



जमुई।भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन ने शुक्रवार को जमुई जिला पदाधिकारी नवीन कुमार से उनके आवास पर आत्मीय मुलाकात की। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना करने के बाद लौटने के क्रम में वे डीएम आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच खेल और विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान ईशान किशन ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर, खेल यात्रा और क्रिकेट के मैदान पर अर्जित अनुभवों को साझा किया। वहीं जिला पदाधिकारी ने जमुई जिले की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उन्हें परिचित कराया। डीएम ने भगवान महावीर की जन्मस्थली के रूप में जमुई की विशिष्ट पहचान के साथ नागी-नकटी पक्षी आश्रयणी, गिद्धेश्वर वन्य क्षेत्र और पंचभूर झरना सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेषताओं और संभावनाओं की जानकारी दी। जमुई की प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता और धार्मिक विरासत के बारे में जानकर ईशान किशन ने काफी रुचि दिखाई। उन्होंने जिले की पर्यटन संभावनाओं की सराहना करते हुए भविष्य में दोबारा जमुई आने की इच्छा भी व्यक्त की। यह मुलाकात जिले की पर्यटन पहचान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की आर्थिक संभावनाओं को मिलेगी नई उड़ान – अनिल अग्रवाल

गया।वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किये गये एक पोस्ट में FICCI में उद्योग जगत को प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपने विचार प्रकट करते हुए भारत की आर्थिक विकास दर को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के अधिक निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि निजी क्षेत्र के प्रबंधन से उत्पादकता में सुधार, रोजगार सृजन और MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। उनका सुझाव है कि निजीकरण के साथ दो शर्तें अनिवार्य होनी चाहिये जिसमें कर्मचारियों की छंटनी न हो और रोजगार के अवसरों में तीन गुना वृद्धि हो। उन्होंने कॉरपोरेट अधिग्रहण के विकल्प के रूप में आम जनता को शेयर आवंटित करने का भी सुझाव दिया है। उनके अनुसार निजीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकारी कर्ज कम करने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिये किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के भरोसे पर आधारित व्यवस्था के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए अग्रवाल ने लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के स्थान पर स्व-प्रमाणन और सरल नियमों को अपनाने की वकालत की है। उनका मानना है कि सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और ऑडिट के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये ताकि कारोबार और नये उद्योग तेजी से शुरू हो सकें और उसका विस्तार हो सके। अग्रवाल ने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिये एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप्स को अपनी खोजों को ONGC और हिंदुस्तान जिंक जैसी स्थापित कंपनियों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिये, जिनके पास बड़े पैमाने पर खनन और प्रोसेसिंग में निवेश करने की क्षमता है। उनका मानना है कि इससे सैकड़ों स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्यमिता के नये अवसर पैदा होंगे। और भारत का घरेलू संसाधन तंत्र मजबूत होगा। अपने पोस्ट के अंत में अग्रवाल ने उद्योग जगत, सरकार और नागरिकों से निजीकरण स्व-प्रमाणन और एक्सप्लोरेशन को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है। खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में 'जय जवान, जय किसान' आंदोलन की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि और भारतीय रुपये को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया।

एसबीआई ने 1,540 जूनियर एसोसिएट्स की नियुक्ति की, वित्त वर्ष 2027 में 12 हजार कर्मचारियों की भर्ती का लक्ष्य



पटना। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने देशभर में विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित वर्गों के 1,540 जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) की नियुक्ति की घोषणा की है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रिक्त बैकलॉग पदों को भरने के लिए यह अभियान चलाया गया। बैंक का उद्देश्य निर्धारित समयसीमा में आरक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के साथ कार्यबल में सामाजिक समावेश और विविधता को बढ़ावा देना है। एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा कि सामाजिक समावेश और समान अवसर एक मजबूत संगठन की बुनियादी जरूरतें हैं। विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को बैंक से जुड़ने और देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर मिलेगा। नवनियुक्त कर्मचारियों से बैंक की शाखाओं में ग्राहकों से जुड़े कार्यों की क्षमता बढ़ेगी और बैंकिंग सेवाएं अधिक सुगम एवं प्रभावी होंगी। चयन प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा 16 सितंबर और मुख्य परीक्षा 29 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 में क्लर्क और अधिकारी संवर्ग में करीब 11 हजार से 12 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना बनाई है। इसके अलावा कारोबार के विस्तार को देखते हुए वर्ष के दौरान 200 से 250 नई शाखाएं खोलने का भी लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि एसबीआई में वर्तमान में करीब 2.47 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। बैंक का कहना है कि नई नियुक्तियों और शाखा विस्तार से उसकी परिचालन क्षमता तथा देशभर में ग्राहकों तक पहुंच मजबूत होगी।

जमुई डीएम नवीन ने जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं

नई सोच एक्सप्रेस



जमुई।आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर शुक्रवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत संचालित 'सबका सम्मान–जीवन आसान' पहल के अंतर्गत आयोजित इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि-राजस्व, आवागमन के रास्ते पर अवरोध, नाली निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। इसके अलावा विद्यालय की जांच कराने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने, आवास संबंधी समस्याओं तथा विद्युत तार की मरम्मत कराने को लेकर भी आवेदन दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई करने तथा प्रत्येक मामले के निष्पादन की अद्यतन स्थिति से उन्हें अवगत कराने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतों की नियमित निगरानी हो सके और आवेदकों को समयबद्ध राहत मिल सके। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राजगीर महोत्सव में लूम सोलर के सोलर प्रोडक्ट्स, घरों, खेती और कारोबार के लिए मिलेंगे समाधान

नई सोच एक्सप्रेस



राजगीर।हरियाणा की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लूम सोलर, जो सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी बनाती है, इस वर्ष राजगीर महोत्सव 2026 में हिस्सा ले रही है। बिहार में घरों, खेती और बिज़नेस की बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने सोलर प्रोडक्ट्स और समाधान लेकर आई है। 26 से 28 नवंबर तक आयोजित इस महोत्सव में लूम सोलर का स्टॉल नंबर 36, स्टेट गेस्ट हाउस ग्राउंड, राजगीर में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में घरेलू उपभोक्ता, बिज़नेस ओनर्स, किसान, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, होटल, स्कूल और फैक्ट्री संचालक आकर अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर समाधान की जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के स्टॉल पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और पीएमएफएमई जैसी सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध संभावनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा, सोलर लोन, हाइब्रिड सोलर सिस्टम, आटा चक्की और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) जैसे विकल्पों की जानकारी भी उपलब्ध है। बिहार में बिजली की जरूरत और इस्तेमाल के बदलते पैटर्न को देखते हुए लूम सोलर ऑन-ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध करा रही है। लूम सोलर के को-फाउंडर अमोद आनंद ने कहा, "राजगीर महोत्सव बिहार के लोगों से सीधे जुड़ने और उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारा प्रयास है कि सोलर एनर्जी केवल घरों तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों, छोटे व्यवसायों, होटलों, स्कूलों और बड़ी फैक्ट्रियों तक भी पहुंचे।

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान आयोजित, छात्र-छात्राओं को दिलाया गया सामाजिक बदलाव का संकल्प

नई सोच एक्सप्रेस



समस्तीपुर/ताजपुर।प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बघौनी में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने की, जबकि मंच संचालन विद्यालय के वरीय शिक्षक सरफराज फाजिलपूरी ने किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, इसके कानूनी प्रावधानों तथा बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाध्यापक डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के बचपन, शिक्षा और बेहतर भविष्य को प्रभावित करती है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। इसे समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।शिक्षक सरफराज फाजिलपूरी ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का केंद्र होने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने और समाज की बुराइयों के प्रति जागरूक करने की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की कम उम्र में शादी करने के बजाय उनकी शिक्षा और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दें। इस अवसर पर नवम वर्ग की प्रियंका कुमारी, मुआविया कमर, आरुषि, नादिया, अनुपम ,सपना इत्यादि छात्राओं ने बाल विवाह के दुष्प्रभाव पर नाटक पेश किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक,छात्र एवं छात्राओं ने बाल विवाह नहीं करने और समाज में बाल विवाह रोकने का शपथ लिया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार, सरफराज फाजिलपूरी, अभिषेक वर्मा, विद्यानंद कुमार, दीनबंधु प्रसाद, गुलाम साबिर, पुष्पम कुमारी, सुरुचि कुमारी, सविता पॉल, पम्मी कुमारी, श्रुति आर्या, प्रियंका कुमारी, जीनत प्रवीण, चांदनी परवीन, स्नेहा कुमारी, आदि मौजूद थें

गया जी में योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी को संत समाज ने दी श्रद्धांजलि

नई सोच एक्सप्रेस



गया।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता स्वर्गीय सावित्री देवी को गया जी में संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतरराष्ट्रीय पांच दशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दूधेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी महाराज तथा संतोष नंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में शोकसभा एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें संत-महात्माओं, धर्माचार्यों एवं श्रद्धालुओं ने दिवंगत माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा को संबोधित करते हुए संतों ने सावित्री देवी को धर्मपरायण, संस्कारवान एवं महान मातृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि माता सावित्री देवी के संस्कारों का ही परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ जैसे संत, राष्ट्रसेवक और सनातन धर्म के प्रहरी देश को मिले। मां बच्चों के व्यक्तित्व, विचार और चरित्र की आधारशिला रखती हैं तथा उनके संस्कार जीवनभर प्रेरणा देते हैं। महंत नारायण गिरी जी महाराज एवं संतोष नंद गिरि जी महाराज सहित उपस्थित संतों ने योगी आदित्यनाथ एवं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत माताजी को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सभा के अंत में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्थानांतरण से बदलता है कार्यस्थल, आत्मीयता का रिश्ता नहीं : समरेंद्र सिंह

नई सोच एक्सप्रेस



छपरा।गड़खा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय फेरुसा में शुक्रवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष अविनाश कुमार पिंटू के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। अविनाश कुमार पिंटू का स्थानांतरण रिविलगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय जान टोला में हुआ है। इस अवसर पर शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित करते हुए नए कार्यस्थल के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि स्थानांतरण सरकारी सेवा की एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे शिक्षक का कार्यस्थल जरूर बदलता है लेकिन साथियों के बीच वर्षों में विकसित हुआ स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता कभी नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि अविनाश कुमार पिंटू एक कर्मठ, ऊर्जावान और संगठन के प्रति समर्पित शिक्षक नेता हैं। शिक्षक हितों के प्रति उनकी सक्रियता और साथियों के साथ उनका सहयोगात्मक व्यवहार सराहनीय है। समरेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक केवल विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य नहीं करते बल्कि अपने व्यवहार और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अविनाश कुमार पिंटू नए विद्यालय में भी अपनी कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से अलग पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर शिक्षक नेता विनय कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, प्रीति कुमारी एवं हरि शर्मा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पाठ पढ़ाएगी संविधान पाठशाला

नई सोच एक्सप्रेस



छपरा।संविधान दिवस के अवसर पर सारण जिले की सोनौली पंचायत में बुधवार को 'संविधान पाठशाला' अभियान का शुभारंभ किया गया। रिफॉर्म इंडिया फाउंडेशन की इस पहल के तहत पूरे बिहार में आम नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 26 नवंबर 2027 तक एक वर्ष चलेगा। इसके माध्यम से लोगों को मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी एलबी मांझी उपस्थित रहे। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं रिफॉर्म इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष आकिल इमाम खान ने कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संविधान पाठशाला की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य लोगों को अधिकारों की जानकारी देने के साथ उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि संविधान की सही जानकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। नागरिक जब अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, तभी न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण संभव होगा। सोनौली पंचायत से शुरू हुआ यह अभियान बिहार के विभिन्न जिलों तक पहुंचेगा। अभियान के सफल संचालन के लिए सारण जिले में समन्वय समिति गठित की गई है। शिक्षक डॉ. पिंटू रंजन प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। समिति जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी। कार्यक्रम में डॉ. शंकर तिवारी, पूर्व मुखिया संतोष परमार, सुनील तिवारी, वकार खान, अशरफ खान, शिक्षक विश्वनाथ सिंह, मीर हसन अंसारी, कृष्ण कन्हैया सिंह और श्रीनिवास सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

25 हजार रुपये नहीं देने पर आवास योजना की सूची से नाम काटने का आरोप, पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार

नई सोच एक्सप्रेस



भभुआ।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का उद्देश्य है, लेकिन भभुआ नगर परिषद के वार्ड नंबर-2 में योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड की निवासी बिगना देवी ने आरोप लगाया है कि 25 हजार रुपये नहीं देने के कारण आवास योजना की लाभार्थी सूची से उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिगना देवी, पति विनोद कुमार राम, का कहना है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और उनका नाम बीपीएल सूची में भी दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उनका आरोप है कि कई वर्षों से आवेदन लंबित है और नगर परिषद कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 25 हजार रुपये की मांग की गई थी। कथित तौर पर राशि नहीं देने के कारण उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आर्थिक रूप से संपन्न और पहले से मकान, खेती तथा नौकरी की सुविधा रखने वाले कुछ लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। बिगना देवी ने योजना के तहत बने कुछ मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम अंकित नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है। इससे योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि प्रशासनिक बैठकों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने और योजना की समीक्षा की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तविक जरूरतमंद परिवार लाभ से वंचित हैं। उनका परिवार आज भी पक्के मकान के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लाभार्थी सूची की समीक्षा करने और यदि पैसे की मांग तथा नाम हटाने के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की अपील की है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।

बाल विवाह के खिलाफ जीविका दीदियों ने निकाली जागरूकता रैली



नई सोच एक्सप्रेस

शिवहर।अंतरराष्ट्रीय बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस पर तरियानी प्रखंड में प्रकाश जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड की जीविका दीदियों ने जागरूकता रैली निकालकर बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। प्रखंड परियोजना प्रबंधक अजय शंकर के नेतृत्व में आयोजित रैली के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। अजय शंकर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य में बाधक है। खासकर बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। उन्होंने अभिभावकों को जागरूक करने और बेटियों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने की अपील की। नई चेतना अभियान 5.0 के तहत कार्यक्रम में लैंगिक समानता, महिला अधिकार, हिंसा, भेदभाव और नशे के दुष्परिणामों पर भी चर्चा हुई। जीविका दीदियों ने बाल विवाह, महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा बाल विवाह मुक्त, समानतापूर्ण और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस दौरान जीविका कर्मियों और स्थानीय लोगों की सहभागिता रही।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व मुखिया पति हत्याकांड में मुख्य आरोपित मोहम्मद साहिल 24 घंटे के रिमांड पर, पुलिस कर रही पूछताछ

सहरसा। बनमा ईटहरी थाना क्षेत्र के सरबेला-मुबारकपुर सड़क मार्ग पर हरेवा पंचायत के पूर्व मुखिया पति जावेद इकबाल उर्फ गुड्डू मुखिया की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। थाना कांड संख्या 187/26 के इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित मोहम्मद साहिल को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लेकर पुलिस उससे हत्याकांड से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, हत्याकांड में पुलिस अब तक कई आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, मामले के मुख्य आरोपित मोहम्मद साहिल, पिता मोहम्मद अब्दुल रशीद, ग्राम चिकनी, थाना सौरबाजार, जिला सहरसा निवासी ने पुलिस की लगातार दबिश के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय से आरोपित को रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद मोहम्मद साहिल को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सहनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपित को 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान हत्याकांड के कारणों, घटना में प्रयुक्त हथियार तथा अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपित से पूछताछ के दौरान हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है।

दो महीने से वन विभाग को छका रहा गैंडा, यूपी सीमा में मिले ताजे पगमार्क

» पिपरासी में दूसरे दिन भी वनकर्मियों ने चलाया सर्च अभियान, पांच किमी दूर चिरवहिया सरेह तक पहुंचने का अनुमान; दहशत में किसान, खेती का काम प्रभावित

पिपरासी। प्रखंड क्षेत्र में पिछले दो महीने से विचरण कर रहा गैंडा वन विभाग की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। गैंडे की तलाश में वनकर्मी लगातार संभावित ठिकानों पर सर्च अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन भी टीम ने गैंडे को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग इलाकों में पगमार्क की तलाश की। इस दौरान यूपी के चिरवहिया सरेह में गैंडे के ताजे पगमार्क मिले। इनके कुछ घंटे पहले के होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि, पगमार्क के आधार पर काफी तलाश के बाद भी गैंडा नजर नहीं आया। पूर्व उपप्रमुख विजय कुशवाहा के अनुसार, गुरुवार सुबह पीपी तटबंध स्थित गुप्ता जी के ठोकर के पास नाले में मछली पकड़ रहे मछुआरों को गैंडे ने दौड़ा लिया था। इसके बाद शुक्रवार को यूपी के चिरवहिया सरेह में मिले पगमार्क से अनुमान लगाया जा रहा है कि गैंडा वहां से करीब पांच किलोमीटर की दूरी तय कर यूपी सीमा में पहुंच गया है। **लोकेशन बदलने से ट्रैकिंग में परेशानी:** लगातार लोकेशन बदलने के कारण वन विभाग की टीम को गैंडे की सटीक स्थिति का पता लगाने में परेशानी हो रही है। पिछले दो महीनों से वनकर्मी और विशेषज्ञ उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है। पूर्व उपप्रमुख ने रेस्क्यू में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए वन विभाग की कार्यशैली पर चिंता जताई है। **गैंडे की दहशत से खेती भी प्रभावित:** गैंडे के दियारा क्षेत्र से निकलकर रिहायशी इलाकों के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग खेतों में जाने से भी सतर्कता बरत रहे हैं। इसका असर खेती-किसानी पर पड़ रहा है। कृषि कार्य पिछड़ने से किसान भी चिंतित हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि गैंडा किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। **सुरक्षित रेस्क्यू की हो रही कोशिश:** रेंजर नसीम अख्तर ने बताया कि गैंडे के पगमार्क मिलने के बाद वनकर्मियों की टीम उसके मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी है। गैंडे को किसी तरह की चोट या नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के कारण अभियान में सावधानी बरतनी पड़ रही है।

पिपरासी में बदलेगी स्कूलों की कमान, अब सीनियर शिक्षक संभालेंगे प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी

» सात उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में जूनियर शिक्षकों के प्रभार पर उठे सवाल, बीईओ ने सभी स्कूलों से मांगी रिपोर्ट

पिपरासी। प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अब प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी वरिष्ठ शिक्षकों को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत जूनियर शिक्षकों को उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार छोड़ना पड़ सकता है। बीडीओ सह प्रभारी बीईओ अनिमेश ने इस संबंध में पहल करते हुए प्रखंड के सभी संबंधित विद्यालयों से रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार, पिपरासी प्रखंड के सात मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया है। इन स्कूलों में अब 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। उत्क्रमण के बाद विद्यालयों में उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। इसके बावजूद कई विद्यालयों में मध्य विद्यालय के जूनियर शिक्षक ही उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार संभाल रहे हैं। जबकि इन स्कूलों में उनसे वरिष्ठ शिक्षक भी पदस्थापित हैं। इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी की जा रही है। विभाग का मानना है कि विद्यालयों में उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षकों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए पहले सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरीयता और वर्तमान प्रभार की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। इधर, बीईओ की ओर से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद लंबे समय से प्रधानाध्यापक का प्रभार संभाल रहे जूनियर शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद वरिष्ठ शिक्षकों को प्रभार सौंपने के लिए जिला शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। **जल्द जिला को भेजी जाएगी अनुशंसा:** प्रभारी बीईओ अनिमेश ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद वरीयता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार देने के लिए जिला को अनुशंसा भेजी जाएगी।

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम

अररिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के मौके पर शुक्रवार को फारबिसगंज अनुमंडल प्रशासन की ओर से बाल विवाह के खिलाफ विशेष जागरूकता कार्यक्रम के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे अनुमंडल को बाल विवाह से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। यह कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त अररिया जिला और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुहिम के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जागरण कल्याण भारती, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन तथा अनुमंडल प्रशासन फारबिसगंज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी अनुमंडलवासियों से अपील की गई कि वे न केवल अपने परिवार में कम उम्र में शादी रोकें, बल्कि समाज में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

बिहार में जुटेंगी देशभर के सभी महिला आयोग की अध्यक्ष

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। बिहार के सभी जिलों में प्री-मैरिटल काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों के लिए काउंसलर को प्रशिक्षण राष्ट्रीय महिला आयोग देगा। अगले दो महीने में इसकी शुरूआत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने गुरुवार को पटना स्थित बिहार म्यूजियम में आयोजित बैठक के दौरान दी। बैठक में महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। विजया रहाटकर ने बिहार म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग हर चार महीने में देशभर के महिला आयोगों की अध्यक्षों, सचिवों और सदस्यों के साथ संवाद करता है। महिलाओं को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस बार कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए 23 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय ह्यशक्ति संवादह्ल कार्यक्रम की मेजबानी बिहार राज्य महिला आयोग करेगा। इसका आयोजन 27 से 29 नवंबर तक राजगीर में किया जा रहा है।कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। देशभर से 150 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।शक्ति संवाद की शुरूआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हुई थी। इसके बाद मुंबई, नई दिल्ली और श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। राजगीर में इसका पांचवां संस्करण आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में लिव-इन रिलेशनशिप पर न्यायिक दृष्टिकोण विषय पर विशेष सत्र होगा। इसमें इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों, न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों और इस व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों एवं संरक्षण पर चर्चा की जाएगी।इसके अलावा जेलों में बंद महिलाओं के अधिकार, कानून से संघर्षरत बच्चों (सीसीएल) और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार जैसे विषयों पर भी विशेष प्रस्तुतियां होंगी।शक्ति संवाद का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के बीच संवाद और समन्वय मजबूत करना है। इसमें महिलाओं से जुड़े मामलों, उनकी समस्याओं और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही महिला कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो. अप्सरा ने बताया कि कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों के महिला आयोगों के सामने आने वाले मामलों और उनके समाधान के तरीकों पर चर्चा होगी। नई तकनीक के इस्तेमाल से महिला संबंधी मामलों के समाधान को लेकर वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी।तीन दिवसीय कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और महिला संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर पैनल चर्चा होगी। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि अपने अनुभव और कार्यप्रणाली साझा करेंगे।

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में सियासी बहस तेज : निशांत कुमार

नई सोच एक्सप्रेस



फतुहा। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता निशांत कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी का अधिकार है, न कि किसी सरकार की मेहरबानी। वर्षों से महिला सशक्तीकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन अब जरूरत है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में वास्तविक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। निशांत कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण को राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान और चुनावी लाभ-हानि से ऊपर रखना होगा। महिलाओं को केवल चुनाव प्रचार और राजनीतिक सभाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केवल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन से है। परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। विशेषकर उन राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के स्वरूप, संवैधानिक आधार और इसे लागू करने की समयसीमा को लेकर सरकार को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। संसद में होने वाले संवैधानिक बदलावों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित में पारदर्शिता के साथ निर्णय लेना चाहिए। निशांत कुमार ने कहा कि संसद का विशेष सत्र केवल विधेयक पारित करने की औपचारिकता नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापक चर्चा हो, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और जनता के सामने सभी प्रावधान स्पष्ट किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती बड़े राजनीतिक फैसलों से नहीं, बल्कि उनके निष्पक्ष क्रियान्वयन और आम जनता को मिलने वाले लाभ से तय होती है। देश को अब राजनीतिक नारों के बजाय निष्पक्ष नीति और ठोस परिणामों की जरूरत है।

एकमा मोबिलिटी फाउंडेशन 28 और 29 नवंबर 2026 को पटना में तीसरा आफ्टर मार्केट एक्सपो करेगा

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। एकमा मोबिलिटी फाउंडेशन, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक पहल है, ने आज पटना आफ्टर मार्केट एक्सपो की घोषणा की। यह एक्सपो 28 और 29 नवंबर, 2026 को पटना के होटल पाटलिपुत्र एक्सोटिका में आयोजित होगा। दो दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली प्रमुख कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, वर्कशॉप और आफ्टरमार्केट से जुड़े अन्य लोग शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी अच्छी गुणवत्ता वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स दिखाने, उद्योग से जुड़ी जानकारी साझा करने और बिहार में कारोबार के नए संबंध बनाने का एक मंच प्रदान करेगी। इस मौके पर एकमा की आफ्टरमार्केट सब-कमेटी के चेयरमैन और स्टीलबर्ड इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानव कपूर ने कहा, बिहार एक अहम ऑटोमोबाइल बाजार के रूप में उभर रहा है। अक्टूबर 2026 तक के 12 महीनों में यहां करीब 15.5 लाख नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। झारखंड के साथ मिलकर यह क्षेत्र भारत के ऑटोमोबाइल आफ्टरमार्केट में करीब 5% का योगदान देता है। यहां लगभग 155 ऑटोमोबाइल डीलर, 1,000 ऑटो पार्ट्स रिटेलर्स और बड़ी संख्या में मरम्मत वर्कशॉप हैं। यह क्षेत्र आफ्टरमार्केट कारोबार को और मजबूत व व्यवस्थित बनाने का बड़ा अवसर देता है। पटना आफ्टर मार्केट एक्सपो उद्योग कोक्षेत्र के कारोबारियों के करीब लाने, अच्छी गुणवत्ता वाले पार्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कारोबार से जुड़े सभी लोगों के बीच बेहतर संपर्क बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।एकमा की आफ्टरमार्केट सब-कमेटी के मेंटर रामाशंकर पांडे ने कहा, ह्यऑटोमोबाइल आफ्टरमार्केट की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहकों को मिलने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी अच्छी और भरोसेमंद हैं। ग्राहकों, मैकेनिकों, रिटेलर्स और अन्य लोगों के बीच असली और अच्छी गुणवत्ता वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

भारत में पहली बार ड्यूल-कंसोल तकनीक से बीटिंग-हार्ट रोबोटिक बाईपास सर्जरी संपन्न

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में स्वदेशी एसएसआई मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम की मदद से दुनिया की पहली ड्यूल-कंसोल, पांच रोबोटिक आर्म वाली बीटिंग-हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास टीइसीएबी सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। मेदांता, गुरुग्राम के डॉ. नितिन कुमार राजपूत और मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर के डॉ. ललित मलिक द्वारा संयुक्त रूप से तथा एसएस इनोवेशंस इंटरनेशनल के संस्थापक, चेयरमैन एवं सीईओ डॉ. सुधीर पी श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में संपन्न इस सर्जरी में मरीज का दिल लगातार धड़कता रहा और हार्ट-लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। मरीज की 15 दिनों की उत्साहजनक रिकवरी के साथ इस उपलब्धि पर डॉ. नरेश त्रेहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, मेदांता ने कहा कि इतनी जटिल बीटिंग-हार्ट टीइसीएबी सर्जरी का सफलतापूर्वक संपन्न होना इस बात का प्रमाण है कि रोबोटिक सर्जरी किस तरह मरीजों के लिए उन्नत हृदय उपचार को कम इनवेसिव बनाने में मदद कर सकती है। यह भारत में हृदय सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सुधीर पी श्रीवास्तव, संस्थापक, चेयरमैन एवं सीईओ, एसएस इनोवेशंस इंटरनेशनल ने कहा कि मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन के अनुरूप यह ऐतिहासिक सर्जरी भारतीय सर्जिकल रोबोटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के हमारे लक्ष्य को करीब लाती है।

सागर में रंगमंच का पांच दिवसीय उत्सव, प्रवीण स्मृति नाट्योत्सव में नाटक और कार्यशाला का होगा आयोजन

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। रंगमंच की गतिविधियों को विस्तार देने और नई पीढ़ी को नाट्य कला से जोड़ने के उद्देश्य से प्रवीण स्मृति नाट्योत्सव 2026 का आयोजन 6 से 10 दिसंबर तक सागर में किया जाएगा। यह जानकारी नाकी उत्सव के अध्यक्ष इंद्रदीप चंद्रवंशी ने बताया कि प्रवीण सांस्कृतिक मंच, पटना एवं डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पांच दिवसीय नाट्योत्सव में नाट्य प्रस्तुतियों के साथ नाट्य कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।दिल्ली और प्रयागराज के बाद इस वर्ष सागर में आयोजित होने वाला प्रवीण स्मृति नाट्योत्सव रंगमंच के विभिन्न पक्षों को सामने लाने का प्रयास है। पांच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में अलग-अलग विषयों और सामाजिक सरोकारों पर आधारित पांच नाटकों का मंचन किया जाएगा।नाट्योत्सव के साथ आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रतिभागियों को रंगमंच की प्रक्रिया, अभिनय और नाट्य प्रस्तुति से जुड़े व्यावहारिक पक्षों को समझने का अवसर मिलेगा। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों और युवा प्रतिभागियों में रंगमंच के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। नाट्योत्सव में 6 दिसंबर को जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित नाटक गुंडा प्रस्तुत किया जाएगा। 7 दिसंबर को कुच्ची का कानून, 8 दिसंबर को नागरदोला, 9 दिसंबर को गबरघिचोर और 10 दिसंबर को ह्यविजयंतीह्ल का मंचन होगा। सभी नाटकों का निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी बिज्येंद्र कुमार टांक करेंगे। रंगकर्मी प्रवीण की स्मृति को समर्पित यह नाट्योत्सव दिल्ली और प्रयागराज के बाद इस वर्ष सागर में आयोजित हो रहा है। आयोजन का उद्देश्य रंगमंच को प्रोत्साहित करना तथा नए कलाकारों और रंगकर्मियों को मंच उपलब्ध कराना है।

लोयोला मॉन्टेसरी स्कूल में लुक व्हाट आई कैन डू कार्यक्रम का आयोजन

नई सोच एक्सप्रेस



पटना। कुर्जी स्थित लोयोला मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ह्यलुक व्हाट आई कैन डू !ह्ल विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से नन्हे विद्यार्थियों को अपनी रोजमर्रा की उपलब्धियों और हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में बच्चों के लिए आकर्षक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिटिजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी रचनात्मक सोच और व्यक्तिगत कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। किसी ने ब्लॉक्स की मदद से आकर्षक टावर और रॉकेट बनाए, तो किसी ने मैग्नेटिक टाइल्स से विभिन्न संरचनाएं तैयार कर अपनी कल्पनाशीलता दिखाई। वहीं, बच्चों ने योगाभ्यास, साइकिलिंग, बागवानी, नृत्य, गायन और चित्रकला जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मुख्य अतिथि सिटिजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार ने कहा कि प्रस्तुतियों के जरिए बच्चों के आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित लकी ड्रॉ में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही, आयोजन में भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चे को सहभागिता पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, अभिभावकों की उपस्थिति और शिक्षकों के सहयोग से पूरा आयोजन आनंदमय एवं यादगार बन गया।

तेलियाहाट बाजार में कार्तिक पूर्णिमा पर दो दिवसीय मेले का आयोजन, प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ समापन

नई सोच एक्सप्रेस



बनमा ईटहरी। थाना क्षेत्र के तेलियाहाट बाजार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित दो दिवसीय मेले का शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ शांतिपूर्ण समापन हो गया। मेले को लेकर तेलियाहाट बाजार सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सवी माहौल बना रहा। दो दिनों तक चले इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मेले के दौरान बाजार में चहल-पहल बनी रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में मेले को लेकर खास उत्साह देखा गया। वहीं, मेले में विभिन्न दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। स्थानीय लोगों ने मेले का आनंद उठाया। शुक्रवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधि-विधान के साथ प्रतिमा विसर्जन किया गया। इसके साथ ही दो दिवसीय मेले का समापन हो गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी। मेले के समापन के बाद बाजार में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस मेले ने एक बार फिर क्षेत्र की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक एकजुटता की झलक पेश की। स्थानीय लोगों के सहयोग से मेला संपन्न हुआ।

सुबह 4:30 बजे मंडल कारा में प्रशासन की दबिश, सभी वार्डों और बैरकों की हुई सघन तलाशी; कुछ नहीं मिला

नई सोच एक्सप्रेस



बगहा। अनुमंडलीय कारा, बगहा में शुक्रवार की अहले सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, एसडीएम चांदनी कुमारी और एसडीपीओ निहार भूषण के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से जेल प्रशासन में हलचल रही। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कारा के सभी वार्डों, बैरकों, बंदियों के रहने वाले स्थानों और पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली। इसके साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की गई। अधिकारियों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। **तलाशी में नहीं मिली कोई प्रतिबंधित सामग्री:** संयुक्त छापेमारी के दौरान अधिकारियों को किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान कारा की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। **आगे भी जारी रहेगा औचक निरीक्षण:** प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और विधि-व्यवस्था के मद्देनजर इस तरह के औचक छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य जेल के अंदर प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखना है।

डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल की जयंती पर समाज के लोगों ने किया नमन, दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि

नई सोच एक्सप्रेस



बगहा। जायसवाल समाज, बगहा की ओर से शुक्रवार को महान इतिहासकार एवं विद्वान डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर सभा का आयोजन कर समाज के लोगों ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित किया और पुष्पमाला व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. जायसवाल ने अपने ज्ञान, शोध और लेखन के माध्यम से भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार और कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर रमाशंकर प्रसाद, नागेंद्र जायसवाल, दीपक जायसवाल, संजय जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, टिंकू जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, विजय कुमार, सुधीर जायसवाल एवं अथर्व जायसवाल सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।

वादों की राजनीति और यूपी के खजाने का गणित



आरती कुमारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अपने-अपने एजेंडे के जरिए मतदाताओं को साधने की कवायद तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने 'जन-मन का मैनिफेस्टो, सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रण पत्र' जारी कर चुनावी बहस को आर्थिक व सामाजिक वादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी 28 पन्नों के घोषणापत्र में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, महिला, किसान, गरीब और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। घोषणापत्र का मूल संदेश सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक राहत और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के इर्द-गिर्द केंद्रित है। हालांकि, इन वादों की राजनीतिक आकर्षकता के साथ उनकी वित्तीय व्यवहार्यता पर भी बहस शुरू हो गई है। सवाल केवल यह नहीं है कि घोषणाएं कितनी लोकप्रिय हैं, बल्कि यह भी है कि सत्ता में आने पर इन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे? सपा के घोषणापत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ना तय है। पात्र महिलाओं और बुजुर्गों को सालाना 40 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने, अगले पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, स्नातक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिलों की पूरी माफी और तत्काल किसान कर्जमाफी की घोषणा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा, पांच रुपये में भोजन की थाली वाली समाजवादी कैंटीन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली और बंद पड़े 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का संकल्प भी लिया गया है। इन घोषणाओं के जरिए पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक सुरक्षा और सरकारी सहायता का भरोसा मजबूत करने का प्रयास किया है।

राहत के वादे, लेकिन खर्च का अनुमान अलग-अलगः घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के आकलन पर राजनीतिक दावों और वित्तीय विश्लेषण के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। सपा की घोषणापत्र समिति के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का दावा है कि प्रमुख घोषणाओं को लागू करने के लिए सालाना लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश के करीब नौ लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के मुकाबले यह राशि बहुत बड़ी नहीं है और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के जरिए इसे जुटाया जा सकता है। सपा के घोषणापत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ना तय है। पात्र महिलाओं और बुजुर्गों को सालाना 40 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने, अगले पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, स्नातक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिलों की पूरी माफी और तत्काल किसान कर्जमाफी की घोषणा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा, पांच रुपये में भोजन कीथाली वाली समाजवादी कैंटीन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली और बंद पड़े 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का संकल्प भी लिया गया है। इन घोषणाओं के जरिए पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक सुरक्षा और सरकारी सहायता का भरोसा मजबूत करने का प्रयास किया है।

राहत के वादे, लेकिन खर्च का अनुमान अलग-अलगः घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि के आकलन पर राजनीतिक दावों और वित्तीय विश्लेषण के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। सपा की घोषणापत्र समिति के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का दावा है कि प्रमुख घोषणाओं को लागू करने के लिए सालाना लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उनका तर्क है कि उत्तर प्रदेश के करीब नौ लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के मुकाबले यह राशि बहुत बड़ी नहीं है और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के जरिए इसे जुटाया जा सकता है। इसके विपरीत, स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषकों के शुरुआती आकलन में इन वादों को एक साथ लागू करने पर सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है। यह अंतर बताता है कि घोषणाओं की लागत का आकलन केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि लाभार्थियों की संख्या, पात्रता के मानदंड, योजना के क्रियान्वयन, मौजूदा योजनाओं के साथ समायोजन और दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों के आधार पर होना चाहिए। महिलाओं और बुजुर्गों को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा ही बजट के लिहाज से बेहद अहम है। यदि पात्र लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंचती है, तो इस योजना पर सालाना 60 हजार करोड़ रुपये से लेकर एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक खर्च हो सकता है। हालांकि, वास्तविक खर्च लाभार्थियों की संख्या और योजना के दायरे पर निर्भर करेगा। इसी तरह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर सालाना 12 हजार से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। किसान कर्जमाफी, मुफ्त सिंचाई बिजली और बकाया बिलों की माफी का असर बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और राज्य सरकार के अनुदान पर भी पड़ेगा।

नौकरियां और पेंशन, स्थायी खर्च की चुनौतीः 25 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ सरकारी खजाने पर दीर्घकालिक दायित्व भी जुड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लाभों का खर्च नियुक्तियों के साथ लगातार बढ़ता रहेगा। पांच वर्षों में नियुक्तियों का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागवार रिक्तियों, भर्ती प्रक्रिया, पदों की स्वीकृति और वित्तीय उपलब्धता का स्पष्ट खाका जरूरी होगा। बेरोजगार स्नातकों को हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता देने की घोषणा भी लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बड़ी वित्तीय योजना बन सकती है। यदि पात्र युवाओं की संख्या अधिक हुई, तो यह खर्च भी राज्य के राजस्व बजट पर दबाव बढ़ाएगा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का सवाल इससे भी अधिक संवेदनशील है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसकी बहाली से भविष्य में पेंशन देनदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे फैसले का आकलन केवल मौजूदा साल के खर्च के आधार पर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में बनने वाले वित्तीय दायित्वों के आधार पर करना होगा।

बजट की वास्तविक स्थिति और सीमित गुंजाइशः उत्तर प्रदेश के वित्तीय ढांचे पर नजर डालें तो तस्वीर इतनी सरल नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल शुद्ध व्यय लगभग 8,50,901 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि सकल बजट का आकार लगभग 9.12 से 9.13 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। राज्य की शुद्ध प्राप्तियां लगभग 7,32,420 करोड़ रुपये हैं और राजकोषीय घाटा 1,18,481 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत है। बजट का बड़ा हिस्सा पहले से निर्धारित खर्चों में जाता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध व्यय पर लगभग 3,53,743 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार के सामने हर साल ऐसी बड़ी राशि की व्यवस्था करने की चुनौती रहती है, जिसे सामान्य प्रशासनिक या विकासात्मक जरूरतों के लिए आसानी से कम नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में भी निरंतर खर्च जरूरी है। शिक्षा के लिए बजट का लगभग 12.4 प्रतिशत, कृषि के लिए नौ प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए छह प्रतिशत आवंटन जैसी व्यवस्थाएं राज्य की विकास प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। ऐसे में किसी नई बड़ी योजना के लिए धन जुटाना केवल बजट के आकार को देखकर तय नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों, पहले से निर्धारित खर्च, केंद्र से मिलने वाली सहायता, कर्ज की सीमा और योजनाओं की प्राथमिकता का समग्र आकलन जरूरी है।

पूंजीगत निवेश पर पड़ सकता है असरः आर्थिक नीति में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्व व्यय में पेंशन, वेतन, सब्सिडी, मुफ्त बिजली और नकद सहायता जैसी मदें शामिल होती हैं, जबकि पूंजीगत व्यय से सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली उत्पादन और औद्योगिक ढांचे का निर्माण होता है। पूंजीगत निवेश अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक क्षमता बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश के बजट में बुनियादी ढांचे और पूंजीगत कार्यों के लिए लगभग 1.78 से दो लाख करोड़ रुपये तक का प्रावधान बताया गया है। यदि नई सरकार को घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त धन जुटाना पड़े, तो यह मौजूदा पूंजीगत बजट के बराबर या उससे भी बड़ा वित्तीय दबाव पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राजकोषीय घाटे की सीमा भी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण बाधा है। वित्तीय अनुशासन के तहत राज्य को राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखना होता है। यदि घाटा बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है, तो नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के विकल्प भी सीमित होंगे। सरकार कर संग्रह बढ़ा सकती है, गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर सकती है, सरकारी संपत्तियों से आय बढ़ा सकती है, केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकती है या योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है। लेकिन इन विकल्पों की अपनी सीमाएं हैं। टैक्स बढ़ाने का फैसला आम जनता और उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, जबकि विकास योजनाओं में कटौती से राज्य की आर्थिक गति प्रभावित हो सकती है।

चुनावी वादों की कसौटी पर आर्थिक जवाबदेहीः लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का घोषणापत्र जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं का दस्तावेज होता है। सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की आर्थिक मजबूती जैसे मुद्दों पर घोषणाएं करना स्वाभाविक है। आर्थिक असमानता और महंगाई के बीच राहत की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए ऐसी योजनाएं महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन किसी भी घोषणा की विश्वसनीयता तभी मजबूत होती है, जब उसके साथ वित्तीय स्रोत, लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान, समयसीमा और क्रियान्वयन की योजना भी सामने हो। सपा का 80 हजार करोड़ रुपये का अनुमान और वित्तीय विश्लेषकों की 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपये की संभावित लागत के बीच अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आर्थिक प्राथमिकताओं और वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि का भी है। यदि वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, पात्रता तय की जाती है, मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय किया जाता है और राजस्व संग्रह बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाते हैं, तो वित्तीय दबाव को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

लोकतंत्र का विस्तार या राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण : परिसीमन, महिला आरक्षण और संघीय संतुलन की चुनौती



आचार्य अशोक चौधरी प्रियदर्शी, कटिहार, बिहार

भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे संवैधानिक विमर्श के दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक देश की राजनीतिक संरचना, राज्यों के प्रतिनिधित्व और संसद की शक्ति-संतुलन व्यवस्था पर पड़ सकता है। लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर प्रस्तावित राजनीतिक एवं विधायी पहल ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह प्रश्न केवल संसद की सीटें बढ़ाने अथवा चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तीकरण और राज्यों के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार द्वारा 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की घोषणा के बाद परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अप्रैल में संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था। अब पुनः इस विषय पर पहल की संभावना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को तीव्र कर दिया है। सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने तथा लोकसभा की संख्या में वृद्धि के माध्यम से प्रतिनिधित्व का विस्तार करना बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष और कुछ क्षेत्रीय दल राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन तथा प्रस्तावित प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधियों की संख्या को जनसंख्या तथा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करना है, ताकि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि के निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बना रहे। भारत में जनसंख्या वृद्धि और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण परिसीमन का प्रश्न समय-समय पर उठता रहा है। लेकिन वर्तमान विवाद इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के अनुपात और राजनीतिक प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण और विकास के क्षेत्र में राज्यों का प्रदर्शन समान नहीं रहा है। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, परिवार नियोजन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां अधिक गंभीर रही हैं। यदि भविष्य में लोकसभा की सीटों का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है और जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के राजनीतिक हिस्से पर दबाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा करती है। क्या जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से प्राप्त किया, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान की आशंका से चिंतित होना चाहिए? क्या विकास और जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय नीतियों के सफल क्रियान्वयन के बाद राज्यों को राजनीतिक असंतुलन का सामना करना उचित होगा? इस प्रश्न का समाधान केवल जनसंख्या के आंकड़ों से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण संघीय व्यवस्था और व्यापक राष्ट्रीय सहमति से होना चाहिए। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धांत जनसंख्या के अनुरूप लोकतांत्रिक समानता है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघ में प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं हो सकता। राज्यों की राजनीतिक पहचान, क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता और संघीय संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, जिसमें किसी राज्य की राजनीतिक आवाज कमजोर न हो और सभी राज्यों को राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक भागीदारी मिले। महिला आरक्षण का प्रश्न इस बहस का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से अपेक्षाकृत कम रही है। महिलाओं को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में आवश्यक कदम है। महिला आरक्षण कानून इस ऐतिहासिक असमानता को दूर करने की महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के कारण उसके क्रियान्वयन में विलंब और राजनीतिक विवाद उत्पन्न होना चिंता का विषय है। महिला सशक्तीकरण केवल सीटों के आरक्षण से पूर्ण नहीं होगा। महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के अवसर भी मिलने चाहिए। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीतिगत प्राथमिकताओं, सामाजिक समस्याओं और विकास की दृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। इसलिए महिला आरक्षण को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बनाने के बजाय राष्ट्रीय सहमति का आधार बनाया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि महिला आरक्षण के भीतर सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर व्यापक विचार हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति पर गंभीर विमर्श होना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों के प्रभावशाली परिवारों अथवा संपन्न वर्गों की महिलाओं तक नेतृत्व के अवसर सीमित न रहें, बल्कि सामान्य सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को भी राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिले। परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वासपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र परिसीमन आयोग, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान, सार्वजनिक परामर्श, राज्यों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के बीच संवाद आवश्यक है। संसद में प्रस्तुत विधेयक की वास्तविक भाषा और प्रावधानों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। यदि राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानुपातिक वृद्धि अथवा उनके वर्तमान राजनीतिक हिस्से की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है, तो उसे विधायी प्रावधानों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। लोकतंत्र केवल बहुमत की शक्ति का नाम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अल्पमत की आवाज, राज्यों के अधिकार, संवैधानिक मर्यादा और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व भी उतने ही आवश्यक हैं। संविधान संशोधन जैसे दूरगामी निर्णय केवल संख्याबल के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय सहमति और संवैधानिक भावना के अनुरूप किए जाने चाहिए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और परिणामों का स्वतंत्र तथा संतुलित मूल्यांकन होना चाहिए। महिला आरक्षण को अनावश्यक रूप से विलंबित नहीं किया जाना चाहिए और परिसीमन के नाम पर राज्यों के बीच राजनीतिक असंतुलन भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करना ही राजनीतिक नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा है। आज भारत को ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें जनसंख्या, विकास, महिला सशक्तीकरण, क्षेत्रीय समानता और राष्ट्रीय एकता परस्पर विरोधी न बनें। परिसीमन की प्रक्रिया यदि न्यायपूर्ण, पारदर्शी और व्यापक सहमति के साथ संपन्न होती है, तो यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। लेकिन यदि इसे राजनीतिक शक्ति के पुनर्वितरण और चुनावी लाभ का माध्यम बनाया गया, तो संघीय व्यवस्था और राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है।

संविधान का संकल्प, दुग्ध क्रांति का सम्मान, नशामुक्त समाज की पुकार और मुंबई हमले की दर्दनाक स्मृति है - 26 नवंबर



जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती है, जो केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि राष्ट्र की स्मृति, संकल्प, संघर्ष और संवेदना का प्रतीक बन जाती है। 26 नवंबर भी ऐसी ही एक तारीख है। यह दिन हमें संविधान के प्रति अपनी निष्ठा याद दिलाता है, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों का बोध कराता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अन्नदाता और पशुपालकों के योगदान का सम्मान करना सिखाता है तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसी तारीख के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा है, जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। निर्दोष नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और विदेशी मेहमानों ने आतंकवाद की क्रूरता का सामना किया। यह हमला केवल मुंबई पर नहीं, बल्कि भारत की एकता, संप्रभुता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला था। इसलिए 26 नवंबर का संदेश बहुआयामी है। एक तरफ संविधान का गौरव है, दूसरी तरफ शहीदों का बलिदान, एक तरफ श्वेत क्रांति के जनक का योगदान है, तो दूसरी तरफ नशे के विरुद्ध सामाजिक संघर्ष। यह दिन हमें उत्सव मनाने के साथ आत्ममंथन करने की भी प्रेरणा देता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के संविधान को अंगीकृत किया था। लगभग तीन वर्षों के विचार-विमर्श, बहस, सुझाव और व्यापक अध्ययन के बाद तैयार हुआ यह संविधान स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बना। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके अंगीकरण की ऐतिहासिक स्मृति में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2015 से केंद्र सरकार ने इस दिन को औपचारिक रूप से संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संविधान केवल कानून की किताब नहीं है। यह भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधने वाला राष्ट्रीय संकल्प है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत जैसे विशाल देश में जहां भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और परंपराओं की अनेक धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं, वहां संविधान राष्ट्रीय एकता का सबसे मजबूत आधार है। डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। लेकिन संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संविधान सभा के सामूहिक चिंतन और लोकतांत्रिक संवाद का परिणाम था। इसमें अनेक विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों और दूरदर्शी प्रतिनिधियों का योगदान शामिल है। संविधान दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम संविधान को केवल समारोहों, भाषणों और सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रख रहे हैं? संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है उसके मूल्यों को व्यवहार में उतारना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो, असहमति को देशद्रोह न माना जाए, कानून के सामने सभी समान हो, महिलाओं और कमजोर वर्गों को न्याय मिले तथा किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। यही संविधान की वास्तविक प्रतिष्ठा है। लोकतंत्र में अधिकारों की मांग जितनी जरूरी है, नागरिक कर्तव्यों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, कानून का सम्मान, सामाजिक सद्भाव, मतदान में भागीदारी और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। संविधान की मजबूती केवल न्यायालयों और संसद से नहीं, बल्कि उन करोड़ों नागरिकों से सुनिश्चित होती है, जो उसके आदर्शों को अपने आचरण में अपनाते हैं। 26 नवंबर का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। यह दिन भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था। उन्होंने भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से विश्व के अग्रणी दुग्ध उत्पादक देशों में पहुंचाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। डॉ. कुरियन ने यह साबित किया कि ग्रामीण भारत की वास्तविक ताकत उसके खेतों, पशुधन और मेहनतकश किसानों में छिपी है। गुजरात के आनंद से शुरू हुआ सहकारी दुग्ध आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। अमूल जैसे सहकारी मॉडल ने लाखों पशुपालकों को बाजार से जोड़ा और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। श्वेत क्रांति केवल दूध उत्पादन बढ़ाने का अभियान नहीं था। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, छोटे किसानों की आमदनी और सहकारिता की शक्ति का उदाहरण भी बना। गांव की वह महिला, जो सुबह-शाम पशुओं की देखभाल करती है, दूध निकालती है और परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, वास्तव में इस क्रांति की महत्वपूर्ण नायिका है। भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में आज अग्रणी है। यह उपलब्धि करोड़ों पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, सहकारी समितियों, वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सा सेवाओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। लेकिन उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाएं, नस्ल सुधार, उचित मूल्य और दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। छोटे पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुग्ध व्यवसाय को कृषि का पूरक ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि के रूप में भी प्रोत्साहित करना होगा। दूध संग्रहण केंद्रों, शीतलन संयंत्रों, प्रसंस्करण इकाइयों और स्थानीय बाजारों का विस्तार करना होगा। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में दुग्ध उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहां गांव-गांव में पशुपालन परिवारों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। सुधा जैसी सहकारी व्यवस्था ने राज्य में दुग्ध व्यवसाय को संगठित पहचान दी है। यदि पशुपालकों को तकनीक, प्रशिक्षण, बाजार और उचित मूल्य मिले तो यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बन सकता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण केवल बड़े उद्योगों और महानगरों में नहीं होगा। इसकी मजबूत नींव गांवों के किसान, पशुपालक और श्रमशील परिवार तैयार करेंगे। 26 नवंबर बिहार के लिए नशामुक्ति के संकल्प का भी महत्वपूर्ण दिन है। राज्य में नशे के विरुद्ध जनजागरूकता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए इस अवसर पर अभियान चलाया जाता है। नशा किसी एक व्यक्ति की बुरी आदत भर नहीं है। यह परिवार की खुशियां छीनता है, आर्थिक स्थिति कमजोर करता है, स्वास्थ्य को नष्ट करता है और सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, नशीले पदार्थ और अन्य व्यसन धीरे-धीरे व्यक्ति की निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। नशे की सबसे बड़ी मार युवा पीढ़ी पर पड़ती है। जिस उम्र में युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, उसी उम्र में नशे की गिरफ्त उनके सपनों को कमजोर कर सकती है। बिहार ने शराबबंदी के माध्यम से नशे के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक पहल की है। लेकिन यह भी समझना होगा कि कानून बनाना और उसका प्रभावी सामाजिक क्रियान्वयन दो अलग-अलग बातें हैं। किसी भी सामाजिक बुराई को केवल दंड के भय से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए जागरूकता, शिक्षा, परामर्श, उपचार और सामुदायिक सहयोग जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण रखे, अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और नशे की लत से पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे। वहीं समाज की जिम्मेदारी है कि वह नशे को प्रतिष्ठा या आधुनिकता का प्रतीक मानने की मानसिकता को समाप्त करे। माता-पिता को बच्चों की गतिविधियों, मित्र मंडली और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील रहना होगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशे के दुष्परिणामों पर नियमित चर्चा होनी चाहिए। युवाओं को खेल, संगीत, साहित्य, योग और कौशल विकास से जोड़

संक्षिप्त समाचार

पत्रकार अभिषेक भारती को हिरासत में यातना देने का आरोप, मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग

रांची। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग युवती के कथित यौन शोषण मामले को उजागर करने वाले पत्रकार अभिषेक भारती को सिमडेगा पुलिस द्वारा हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने आयोग से मामले में तत्काल स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकरटांड़ थाना में अभिषेक भारती को मनचाहा बयान देने के लिए घंटों प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि उनके तलवों पर लाठियां बरसाई गईं और उंगलियों के बीच पेंसिल फंसाकर मारपीट की गई। बताया गया है कि अदालत में पेशी के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े। इसके अलावा न्यायालय परिसर में उनकी स्थिति का वीडियो बनाने वाले तीन पत्रकारों के मोबाइल से रिकॉर्डिंग मिटाने का भी आरोप लगाया गया है। मरांडी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अभिषेक भारती को तत्काल समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से उनकी स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने संबंधित थानों एवं न्यायालय परिसर के सीसीटीवी फुटेज, स्टेशन डायरी, न्यायालय के दस्तावेज और अस्पताल के चिकित्सा अभिलेख सुरक्षित रखने की मांग भी की है। साथ ही, मामले से जुड़े सभी पत्रकारों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज कराने का अनुरोध किया है।

संगठन सृजन अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम और धनबाद ग्रामीण के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक



रांची। झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम (ग्रामीण) और धनबाद (ग्रामीण) जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं सांसद केसी वेणुगोपाल ने दोनों नवगठित जिला कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 26 नवंबर को जारी पत्र के अनुसार, पूर्व एआईसीसी सचिव पी. गोपी को पूर्वी सिंहभूम (ग्रामीण) तथा पूर्व एआईसीसी संयुक्त सचिव रणविजय सिंह लोचव को धनबाद (ग्रामीण) जिला कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटियों के विभाजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। अब दोनों पर्यवेक्षक संगठन सृजन अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपेंगे। एआईसीसी महासचिव ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षकों के जिला दौरे और संगठनात्मक परामर्श के दौरान आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मानना है कि इस अभियान से पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

सिमरिया मुख्य चौक पर ट्रक और फ्लाई ऐश लदे ट्रेलर में जोरदार टक्कर, दोनों चालक बाल-बाल बचे



सिमरिया (चतरा)। सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित मुख्य चौक पर शुक्रवार को ट्रक और फ्लाई ऐश लदे ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर धंस गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक बाल-बाल बच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का संभावित कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। अचानक हुई इस टक्कर से कुछ देर के लिए मुख्य चौक पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दोनों चालकों के सुरक्षित बचने से लोगों ने राहत की सांस ली। मुख्य चौक जैसे व्यस्त स्थान पर हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिरहु सीमांत का तीखा मोड़ बना दुर्घटना का कारण, ट्रक पेड़ से टकराया



सिमरिया। सिमरिया अनुमंडल के बिरहु–हजारीबाग सीमांत के समीप स्थित तीखे मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे में बड़ी घटना होने से बाल-बाल बचा घटना के बाद स्थानीय लोगों में सड़क की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।बताया जाता है कि उक्त मोड़ काफी तीखा और घुमावदार होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है। आए दिन इस स्थान पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाते हैं, तो कभी आपस में भिड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त मोड़ पर सड़क की बनावट दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। यदि समय रहते संबंधित विभाग द्वारा मोड़ का सुधार, सड़क चौड़ीकरण, सुरक्षा संकेतक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग एवं सड़क निर्माण एजेंसी से मांग की है कि बिरहु सीमांत के समीप स्थित इस खतरनाक मोड़ का जल्द निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराया जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और राहगीरों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वीर बुली महतो की 241वीं जयंती मनाई, जन्मस्थली पर प्रतिमा स्थापित करने की पहल करेगी आजसू



सिल्ली। झारखंड के महान क्रांतिकारी एवं कोल विद्रोह के अग्रणी सेनानी वीर बुली महतो की 241वीं जयंती शुक्रवार को सिल्ली स्थित आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वीर बुली महतो के वंशज प्रदीप कुमार महतो, स्थानीय युवाओं और उनके जीवन पर शोध कर रहे सिल्ली कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर श्रीकांत महतो को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि वीर बुली महतो जैसे महान क्रांतिकारियों का इतिहास पूरे झारखंड की साझा विरासत है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, शोषण और जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ साहस के साथ संघर्ष किया। जल, जंगल, जमीन और समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका बलिदान आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के अनेक वीर नायकों को इतिहास में उचित सम्मान और पहचान नहीं मिली है। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान से परिचित कराना जरूरी है।

महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की राजनीतिक साजिश कर रही केंद्र सरकार : सतीश पौल मुजनी

नई सोच एक्सप्रेस



रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह मीडिया चेयरमैन सतीश पौल मुजनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून वर्ष 2023 में संसद से पारित हो चुका है, इसके बावजूद परिसीमन की शर्त जोड़कर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। मुजनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पक्षधर रही है। वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित कराया था और 2023 में भी कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून का समर्थन किया। कांग्रेस की मांग है कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं और इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। इसके लिए परिसीमन का इंतजार कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर सकती है, तो परिसीमन की अनिवार्य शर्त हटाकर 2029 से आरक्षण लागू क्यों नहीं करती? सरकार को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए और विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने आशंका जताई कि परिसीमन का असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और देश के संघीय ढांचे पर पड़ सकता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ अन्याय होने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व के अनुपात को अगले 25 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाए। असम परिसीमन का उल्लेख करते हुए मुजनी ने कहा कि वर्ष 2023 में वहां हुए परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में कमी आई। इससे परिसीमन की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग को नजरअंदाज किया। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लेना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। मुजनी ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का मसौदा सार्वजनिक करने, सर्वदलीय बैठक बुलाने और महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके नाम पर परिसीमन की राजनीति और देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने के प्रयास का विरोध करती है। महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन इसकी आड़ में देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी ऐतिहासिक निर्णय : आदित्य साहू

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उनका उचित अधिकार दिलाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। आदित्य साहू ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत झारखंड में लोकसभा की वर्तमान 14 सीटें बढ़कर 21 और विधानसभा की 81 सीटें बढ़कर लगभग 121 हो सकती हैं। इससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और राज्य की आवाज संसद तथा विधानसभा में और मजबूती से उठ सकेगी। उन्होंने कहा कि देश की आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों में समय के साथ बदलाव आया है। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और सीटों की संख्या में वृद्धि से जनप्रतिनिधियों को जनता से बेहतर संपर्क स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के कारण जनप्रतिनिधियों को पूरे क्षेत्र तक पहुंचने में कठिनाइयां होती हैं। परिसीमन से लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। साहू ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो सहित विपक्षी दल परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात को सुरक्षित रखने के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के मुद्दे पर केवल राजनीति की और महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए ठोस पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण केवल सीटों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को नीति निर्धारण, राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को शासन और विकास की प्राथमिकता बनाया है। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी इसी राजनीतिक इच्छाशक्ति और विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है।

ग्रामीण विकास योजनाओं की बदहाली पर भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मांगा जवाब

नई सोच एक्सप्रेस



रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और उनके क्रियान्वयन में सामने आई खामियों को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को घेरते हुए कहा कि सरकार गांवों के विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और जल जीवन मिशन की जमीनी स्थिति बेहद चिंताजनक है। रमाकांत महतो ने कहा कि 11 अगस्त 2026 को विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच मनरेगा के तहत प्रस्तावित 1.02 करोड़ से अधिक कार्यों में से मार्च 2024 तक केवल 27 प्रतिशत ही पूरे हो सके। वहीं, 50.21 लाख से अधिक कार्य अधूरे रह गए, जिन पर 2,633 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की स्थिति भी चिंताजनक है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, अकुशल मजदूरों की 321.84 करोड़ रुपये की मजदूरी मार्च 2025 तक बकाया थी। इसके अलावा मस्टर रोल और माप पुस्तिका के रखरखाव में भी अनियमितताएं सामने आईं। बिना सत्यापित माप के भुगतान किए जाने के मामले भी रिपोर्ट में दर्ज हैं। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 6.32 लाख पात्र ग्रामीण परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए। वर्ष 2016 से 2024 के बीच 15.92 लाख आवास स्वीकृत किए गए, लेकिन जनवरी 2025 तक 15.62 लाख आवास ही पूरे हो सके। वहीं, उपलब्ध 20,199.98 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 14,113 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। महतो ने कहा कि राज्य में 98,067 योजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद दिसंबर 2024 तक केवल 27,249 योजनाएं पूरी हो सकीं। मार्च 2025 तक राज्य के 62.53 लाख ग्रामीण परिवारों में से महज 55 प्रतिशत परिवारों को ही नल से जल का कनेक्शन मिल पाया, जबकि राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत था। रमाकांत महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से सवाल किया कि ग्रामीण मजदूरों को समय पर मजदूरी, गरीब परिवारों को पक्का मकान और गांवों में स्वच्छ पेयजल कब मिलेगा? उन्होंने कहा कि केवल बैठकों और समीक्षा से ग्रामीण विकास नहीं होगा। सरकार को योजनाओं की जमीनी स्थिति सुधारने के साथ लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कैग की रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर जवाब देने की मांग की। महतो ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास संबंधी दावों और गांवों की वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर है। सरकार को लंबित कार्यों और भुगतान की समस्या दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए।

पत्रकार अभिषेक भारती को हिरासत में यातना देने का आरोप, हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग युवती के कथित यौन शोषण मामले को उजागर करने वाले पत्रकार अभिषेक भारती को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के आरोपों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सिमडेगा के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकरटांड़ थाना पुलिस ने अभिषेक भारती पर अदालत में मनचाहा बयान देने का दबाव बनाया और इसके लिए घंटों उनकी पिटाई की। आरोप है कि 26 नवंबर की रात से 27 नवंबर की दोपहर तक उनके तलवों पर लाठियां बरसाई गईं तथा उंगलियों के बीच पेंसिल फंसाकर हाथों पर प्रहार किया गया। उन्हें मुँह के बल लिटाकर भी पीटने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। मरांडी ने बताया कि अदालत में पेशी के दौरान अभिषेक की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने पैरों पर चलने की स्थिति में नहीं थे। आरोप है कि न्यायिक दंडाधिकारी के सामने वह बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया, लेकिन पुलिस पहले उन्हें टाउन थाना ले गई और बाद में सदर अस्पताल पहुंचाया। मरांडी ने उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की प्रामाणिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न्यायालय परिसर में अभिषेक की हालत का वीडियो बना रहे तीन पत्रकारों को टाउन थाने ले जाकर करीब चार घंटे तक बैठाया गया और उनके मोबाइल से रिकॉर्डिंग मिटाने के बाद छोड़ा गया। मरांडी ने इस मामले की भी निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित पत्रकारों के बयान दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता ने सिमडेगा एसपी से सवाल किया कि हिरासत में लेते समय और अदालत में पेश करते समय अभिषेक की शारीरिक स्थिति क्या थी तथा उन्हें किस समय सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने पाकरटांड़ और टाउन थाना के सीसीटीवी फुटेज, स्टेशन डायरी, हिरासत एवं पेशी से जुड़े दस्तावेज और अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड तत्काल सुरक्षित रखने की मांग की। साथ ही स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से जांच कराने और पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति में अभिषेक का बयान दर्ज करने की बात कही। मरांडी ने कहा कि हिरासत में किसी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। यदि हिरासत में यातना देने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पद और प्रभाव की परवाह किए बिना कानूनसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।

अबुआ सरकार में बबुआ का बोलबाला, जनता परेशान

नई सोच एक्सप्रेस



मयूरहंड (चतरा)। जिले के मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड से सरकारी विद्यालयों में कराए जा रहे बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में विभागीय उदासीनता के कारण योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बिना समुचित स्थल निरीक्षण किए ही प्राक्कलन तैयार कर संवेदकों को कार्य आवंटित कर दिया। इसका नतीजा है कि कई विद्यालयों में जरूरत के अनुसार बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की गई, जबकि कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक राशि दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसका उदाहरण उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिग्घी में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि विद्यालय में लगभग 1600 वर्ग फीट बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, जबकि विभाग की ओर से मात्र 1000 वर्ग फीट निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्रखंड क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी आवश्यकता के अनुरूप राशि आवंटित नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो पाना मुश्किल बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने स्थल का सही आकलन क्यों नहीं किया? स्थानीय स्तर पर विभागीय कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य विद्यालयों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि योजना का निर्धारण ही बिना उचित जांच-पड़ताल के किया जाएगा तो सरकारी राशि का सदुपयोग कैसे सुनिश्चित होगा? हैरानी की बात यह है कि इन आरोपों के बावजूद जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि डीएमएफटी फंड से हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है? क्या संबंधित विभाग के अधिकारी स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करते हैं या फिर कागजों पर ही योजनाओं का बंटवारा कर दिया जाता है? ग्रामीणों एवं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आवंटित राशि और वास्तविक जरूरत का मिलान करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं संवेदकों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटोरोला एज 70 नियो



नई सोच एक्सप्रेस

रांची। मोटोरोला ने 34,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 नियो लॉन्च किया। इसे एआई-पावर्ड फोटोग्राफी, आरामदायक क्वाड-कर्व्ड डिजाइन, इमर्सिव डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ हर बारीकी कैद करने के लिए बनाया गया है। इसमें 7000 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है जो टर्बोपावर चार्जिंग के साथ 53 घंटे तक का बैकअप देती है। फोटोग्राफी के लिए ओआईएस युक्त 50 एमपी सोनी एलवाइटीए 710 मुख्य कैमरा और 32एमपी 4के सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ ही एंड्रॉयड 16 पर आधारित इस फोन में गूगल जेमिनी, डॉल्बी एटमॉस और 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। मोटोरोला इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर टी एम नरसिम्हन ने कहा कि यह फोन ग्राहकों तक सार्थक इनोवेशन पहुंचाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एक ही डिवाइस में एआई फोटोग्राफी, आकर्षक डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

नई सोच एक्सप्रेस



खूंटी। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को तोरपा प्रखंड में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश पर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। शिविर में उपस्थित लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बच्चों के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के संबंध में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। कम उम्र में विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होता है।बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम और शशिकला कुमारी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने बाल विवाह की सूचना संबंधित प्राधिकार तक पहुंचाने की अपील की।डीएलएसए के पारा विधिक स्वयंसेवकों ने भी ग्रामीणों को विधिक सहायता और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया। शिविर में बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सामूहिक सहभागिता का आह्वान किया गया।

पारंपरिक ग्राम व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए चार ग्राम प्रधान सम्मानित

नई सोच एक्सप्रेस



खूंटी। झारखंड की पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने, पारंपरिक रीति-रिवाजों के संरक्षण और ग्राम विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सदर अंचल के चार ग्राम प्रधानों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने ग्राम प्रधानों को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। सम्मानित होने वालों में डन्डौल गांव के निकोलस उरांव, फुदी गांव के दाउद मुंडा, कालामाटी गांव के गांगु पहान और सरसजोमा गांव के घासीराय मुंडा शामिल हैं। इन ग्राम प्रधानों ने पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के तहत सामाजिक समरसता बनाए रखने, स्थानीय स्तर पर विवादों के निपटारे में सहयोग करने तथा ग्रामीण समुदाय के बीच आपसी सामंजस्य और सहयोग की भावना मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।इस अवसर पर उपायुक्त ने पारंपरिक ग्राम व्यवस्था की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण समाज में ग्राम प्रधानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे स्थानीय स्तर पर सामाजिक समन्वय स्थापित करने, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और गांवों के विकास में सक्रिय योगदान देते हैं। पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का आपसी सहमति और संवाद के आधार पर समाधान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहायक होता है। उन्होंने ग्राम प्रधानों के योगदान की सराहना करते हुए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संक्षिप्त समाचार

उत्कृष्ट कार्य के लिए कुदलुम पंचायत को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार

खूंटी।ग्राम पंचायत भवन में आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदलुम का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पंचायत राज विभाग की ओर से पंचायत के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह चयन किया गया है।ग्राम पंचायत कुदलुम को आगामी 28 नवंबर को रांची के खेलगांव परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पंचायत भवन की आधारभूत संरचना तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पंचायत को यह सम्मान दिया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कुदलुम पंचायत का चयन होने से पंचायतवासियों में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि से कर्रा प्रखंड के साथ-साथ खूंटी जिले का गौरव भी बढ़ा है। पंचायत के उत्कृष्ट कार्यों को राज्य स्तर पर पहचान मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के विकास के प्रयासों को नई प्रेरणा मिलेगी।

बीएफसीएल 16 महिलाओं को दिलाएगा ब्यूटीशियन प्रशिक्षण

रामगढ़। रामगढ़ जिले की महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड (बीएफसीएल) की ओर से सीएसआर के तहत ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को सुभाष चौक स्थित जावेद हबीब सैलून में आयोजित कार्यक्रम के तहत 16 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रामगढ़ जिले एवं आसपास के क्षेत्रों की 16 लाभार्थी महिलाएं शामिल हुई हैं। छह माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ब्यूटीशियन से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक एवं तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इस क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर तलाश सकें। बीएफसीएल की ओर से इससे पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच की शुरुआत की गई थी। अब दूसरे बैच के शुभारंभ के साथ कंपनी ने स्थानीय महिलाओं को हुनरमंद बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी सीएसआर पहल को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में बीएफसीएल के सीनियर जनरल मैनेजर (सीएसआर) राकेश गुप्ता, सीएसआर अधिकारी शुभम कुमार सहित सीएसआर टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बालिका उच्च विद्यालय मुरपा और आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय कुजू में डायल-112



कुजू। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में बालिका उच्च विद्यालय मुरपा और आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय कुजू में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ओपी के पुअनि आशीष गौतम ने विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अन्य उपस्थित लोगों को डायल-112 की उपयोगिता, महिलाओं से संबंधित अपराध और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए डायल-112 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों और महिला उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के प्रति सजग रहने की जानकारी दी गई। वही साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को अनजान कॉल, फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी, ओटीपी साझा करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने छात्र-छात्राओं से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या साइबर ठगी की जानकारी तत्काल पुलिस को देने तथा दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। मौके पर प्रधानाध्यापक कुलदीप प्रसाद और मिंटू कुमारी मौजूद थे।

एमबी डीएवी विद्यालय, लोहरदगा में भारतीय संविधान दिवस एवं पोक्सो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन



लोहरदगा| एमबी डीएवी विद्यालय लोहरदगा में भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर प्राचार्या प्रेरणा शंखधर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संविधान की महत्ता, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक अमृत बरेक तथा छात्रा अनुष्का कुमारी ने संविधान दिवस पर भाषण प्रस्तुत किया। छात्रा नंदनी कुमारी, अंकिता कुमारी, आकांक्षा कुमारी तथा भारतीय कुमारी ने संविधान पर आधारित पोस्टर तैयार किया। विद्यार्थियों के मध्य संबंधित विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाया गया। छात्र वेद प्रकाश ने संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। इसके पश्चात अक्षिता खत्री ने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति निष्ठा एवं सम्मान की प्रतिज्ञा दिलाई। इसके साथ ही 25 नवंबर 2026 को कक्षा 7 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए पोक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता सत्र का आयोजन प्राचार्या महोदया के मार्गदर्शन में किया गया। विद्यालय की पोक्सो समिति वर्ष 2023 से सक्रिय रूप से कार्यरत है। समिति में अध्यक्ष के रूप में प्राचार्या महोदया, शिक्षक यू.सी. दास, शिक्षिका मीता बसु, विद्यालय के हेड बॉय गौरव कुमार, हेड गर्ल नीलिमा कुमारी तथा एक गैर-शिक्षण कर्मचारी सदस्य शामिल हैं। जागरूकता सत्र में समिति के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता श्री पंकज कुमार अग्रवाल तथा शिक्षक यू.सी. दास ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों, बच्चों की सुरक्षा, अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार तथा इससे संबंधित 'क्या करें और क्या ना करें' के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी असहज या अनुचित परिस्थिति में जागरूक रहने, अपनी बात खुलकर कहने तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय शिक्षक अथवा अभिभावक से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, जागरूक नागरिकता तथा बाल सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करना और विद्यालय में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह विरोधी दिवस पर लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने किए कार्यक्रम और निकाला जागरूकता मार्च

नई सोच एक्सप्रेस



लोहरदगा| भारत को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प के साथ देशभर में चल रही इस मुहिम की गूंज लोहरदगा में भी सुनाई दी। बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नागरिक समाज संगठन लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने जिले में 86 जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए। बाल विवाह से बचाई गई लड़कियों, बाल विवाह रुकवाने में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर बदलाव की वाहक बनी महिला नेतृत्वकर्ताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर बाल विवाह के खिलाफ एकजुटता दिखाई और इस अपराध को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसमें धर्म गुरुओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग DSWO, DCPU, CWC ,AVA ने हिस्सा लिया। लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। इस दौरान निकाले गए कैंडल मार्च में बाल विवाह से प्रभावित महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और समाज के विभिन्न वर्गों के 31939 लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने न केवल बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी समाज को इस अपराध के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। अभियान की खास बात यह रही कि इसमें केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि विवाह समारोहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी हितधारक भी शामिल हुए। पुरोहितों, मौलवियों, हलवाइयों, रसोइयों, सजावट का काम करने वालों, बैंड-बाजा संचालकों, टेंट वालों और शादी के कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों ने न केवल कार्यक्रम में हिस्सा लिया बल्कि शपथ भी ली कि वे किसी भी बाल विवाह में भागीदार नहीं बनेंगे। साथ ही, कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराते हुए लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने कहा, "हम पिछले तीन वर्षों से सरकार और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के साथ मिलकर बाल विवाह के खात्मे के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह केवल एक अपराध को समाप्त करने का अभियान नहीं, बल्कि देश की बच्चियों को उनका बचपन, शिक्षा और अपने भविष्य को चुनने का अधिकार दिलाने की लड़ाई है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हमारी बेटियां शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर हों। बाल विवाह इस राह की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जिले में शुरू हुई हमारी यह मुहिम आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है। हमें विश्वास है कि सरकार, प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयासों से हम अपने जिले को बाल विवाह मुक्त बना सकेंगे।" भारत से शुरू हुई बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के वैश्विक आंदोलन में बदलने की यात्रा पर जेआरसी के राष्ट्रीय समन्वयक रवि कांत ने कहा, "चार सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह जेआरसी और उसके संस्थापक भुवन ऋभु के वर्षों के अथक प्रयासों की एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने के समय भुवन ऋभु भी प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र में मौजूद थे। यह भारत के लिए भी गर्व और उपलब्धि का क्षण था, क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह रोकने के लिए शुरू हुई मुहिम को आज वैश्विक मंच पर मान्यता मिली और यह संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बन गई। यह इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत स्थानीय स्तर से हो सकती है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से वह पूरी दुनिया का आंदोलन बन सकता है।" जेआरसी के 300 से अधिक सहयोगी संगठन देश के 782 जिलों में बाल विवाह के उन्मूलन के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में नेटवर्क ने देशभर में साढ़े छह लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने भी स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और सहयोग से अकेले वर्ष 2024-25 में जिले में 1601 बाल विवाह रुकवाए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की दर का आंकड़ा साल 2019-21 में 23.3 फीसदी था, जो 2023-24 में घटकर 20.1 फीसदी हो गया। अगर लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान की बात की जाए तो ये आंकड़ा 2023-24 में 20.9 था। लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर विक्रम कुमार ने कहा कि बाल विवाह जैसे अपराध को केवल कानून और प्रशासन के भरोसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शादी में शामिल होने वाले पुरोहित से लेकर हलवाई, बैंड-बाजा संचालक और कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक, हर किसी का यह संकल्प जरूरी है कि वह किसी बाल विवाह का हिस्सा नहीं बनेगा। जब समाज एक साथ खड़ा होगा, तभी इस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकेगा।

दुर्घटना में घायल युवा व्यवसायी की इलाज के दौरान मौत



नई सोच एक्सप्रेस

खूंटी। तोरपा थाना क्षेत्र के दियांकल गांव के पास गुरुवार को स्कूटी और बाइक के बीच हुई टक्कर में घायल तोरपा के युवा व्यवसायी विकास कुमार (32) की गुरुवार की रात इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। वह राजेंद्र साहू का बड़ा बेटा था। दुर्घटना में उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफरल अस्पताल तोरपा से रांची रेफर कर दिया गया था। रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उल्लेखनीय है कि विकास कुमार स्कूटी से किसान पाठशाला की ओर से तोरपा स्थित अपने घर लौट रहे थे। दियांकल गांव के पास विकास कुमार स्कूटी लेकर मुख्य सड़क पर पहुंचे, तभी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। छाता नदी मुक्तिधाम में शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

चाईबासा मंडल कारा में 11 टीमों ने की सघन तलाशी

नई सोच एक्सप्रेस



पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस ने गुरुवार देर रात चाईबासा मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू के संयुक्त नेतृत्व में हुए इस अभियान का उद्देश्य जेल की आंतरिक सुरक्षा, बंदियों को मिल रही सुविधाओं और कारा प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लेना था।निरीक्षण के लिए कुल 11 जांच दल गठित किए गए थे। इनमें प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे। सभी दलों ने अपने निर्धारित क्षेत्रों में एक साथ सघन तलाशी अभियान चलाया।जांच के दौरान बंदियों के विभिन्न वार्डों और बैरकों, भोजनालय, जेल अस्पताल, शौचालय तथा अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से पड़ताल की गई। अधिकारियों ने बंदियों के रहने की स्थिति, परिसर की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जांच की गई।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उनसे भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूछताछ की गई। कारा प्रशासन को निर्देश दिया गया कि बंदियों को सभी निर्धारित बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।सघन तलाशी के बावजूद जेल परिसर और बंदी वार्डों से कोई आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने और संभावित लापरवाही की गुंजाइश खत्म करने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

एआईडब्ल्यूसी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में वार्षिक खेल दिवस आयोजित, विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम

नई सोच एक्सप्रेस



पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर स्थित एआईडब्ल्यूसी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 का 22वां वार्षिक खेल दिवस उत्साह और खेल भावना के साथ आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, मार्च पास्ट और ड्रिल के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित शतरंज खिलाड़ी और सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, जमशेदपुर की पूर्व छात्रा नेहा सिंह थीं। वह राष्ट्रीय जूनियर बालिका शतरंज प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा वह बिहार की पहली महिला हैं, जिन्होंने नेशनल 'ए' चैंपियनशिप और राष्ट्रीय सीनियर पुरुष शतरंज टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है।समारोह में एआईडब्ल्यूसी जमशेदपुर कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रांच की अध्यक्ष पारुल मंगल, उपाध्यक्ष विनीता शाह, सदस्य रवीण दुग्गल, एआईडब्ल्यूसी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस की मानद सचिव डॉ. केट्टी भाटेना और मानद कोषाध्यक्ष मिताली चोपड़ा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्या जसबीर कौर गिल, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी भी समारोह में शामिल हुए।कार्यक्रम की शुरुआत रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़कर की गई। इसके बाद विद्यालय के पृथ्वी, अग्नि, रोहिणी और आर्यभट्ट सदनों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। मशाल प्रज्वलन समारोह में आशीष कुमार, अमित गोप, प्रिया कुमारी और अद्याशा राउत ने मशाल वाहक की भूमिका निभाई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अनुशासन, तालमेल तथा टीम भावना का परिचय दिया।प्रधानाचार्या जसबीर कौर गिल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके जरिए बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।समारोह के दौरान मार्च पास्ट विजेता, ओवरऑल चैंपियन, प्रथम एवं द्वितीय उपविजेता, सर्वश्रेष्ठ ड्रिल और सर्वाधिक अनुशासित प्लाटून के नामों की घोषणा की गई। समापन समारोह के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन ने विद्यार्थियों को जीत-हार से आगे बढ़कर निरंतर प्रयास, दृढ़ता, सहभागिता और एकता का संदेश दिया।--

सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत, दोस्त गंभीर

नई सोच एक्सप्रेस



पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में पारडीह काली मंदिर के सामने हुए सड़क हादसे में 19 वर्षीय महेश्वर गोप की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त लल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महेश्वर को मृत घोषित कर दिया। महेश्वर गोप अपने दोस्त लल्लू के साथ गुरुवार रात पटमदा में आयोजित एक पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी समाप्त होने के बाद दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे पारडीह काली मंदिर के सामने उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों युवक स्कूटी से दूर सड़क के अलग-अलग हिस्सों में जा गिरे। दुर्घटना की सूचना रात करीब 12 बजे लल्लू के परिजनों को मिली। वे तत्काल महेश्वर के घर पहुंचे और उसके परिवार को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद महेश्वर के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। वहां स्कूटी सड़क पर गिरी हुई थी, जबकि दोनों युवक घायल अवस्था में पड़े थे। महेश्वर झाड़ियों में फंसा हुआ था। परिजनों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने महेश्वर गोप को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल लल्लू का इलाज जारी है। शुक्रवार को पुलिस ने महेश्वर के शव का पोस्टमार्टम कराया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जवान बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

पहले झारखंडियों को मिलेगा उनका हक-अधिकार, फिर दूसरे राज्यों पर होगा विचार : हेमंत सोरेन

नई सोच एक्सप्रेस



रामगढ़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपने दादा और झारखंड आंदोलन के प्रेरणास्रोत सोबरन मांझी के 69वें शहादत दिवस पर उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा पहुंचे। यहां लुकैयाटांड़ स्थित ऐतिहासिक शहादत स्थल पर उन्होंने सोबरन मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गांडेय विधायक एवं मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद थीं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले को करीब 111 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष शोक का समय है, इसलिए इस बार आयोजन बेहद सादगी के साथ किया जा रहा है। अगले वर्ष इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड के अधिकार, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता और अलग राज्य के लिए हुए संघर्ष को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लुकैयाटांड़ की यह ऐतिहासिक धरती ऐसे बलिदान की साक्षी है, जिसकी गूंज ने झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को नई दिशा दी। 69 वर्ष पहले इसी दिन घने जंगलों में सामंती सोच रखने वाले लोगों ने शिक्षक सोबरन मांझी की हत्या कर दी थी। उस समय घटना को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी शहादत की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। यही चिंगारी आगे चलकर बड़े आंदोलन की प्रेरणा बनी। उन्होंने कहा कि सोबरन मांझी की शहादत ने आदिवासी-मूलवासी समाज को अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इस संघर्ष की अलख लंबे समय तक जीवित रखी। अलग झारखंड राज्य के निर्माण का सफर आसान नहीं था। गिरिडीह, धनबाद, टुंडी, कोल्हान, छोटानागपुर और संथाल परगना सहित राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अलग राज्य की मांग को कभी असंभव बताकर खारिज किया जाता था, उसका निर्माण आदिवासी-मूलवासी और गरीब-गुरबों के संघर्ष से संभव हुआ। आज उसी संघर्ष और शहीदों के परिवारों से निकली नई पीढ़ी राज्य का नेतृत्व कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव के साथ सोबरन मांझी और अन्य आंदोलनकारियों के योगदान को भी नई पीढ़ी को याद रखना चाहिए। राज्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 से 50 वर्ष तक की 50 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि गरीबी से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के राजस्व स्रोतों को बाधित किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से खजाना मजबूत कर जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसके बावजूद झारखंड अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "अब वह झारखंड नहीं है, जहां दूसरे राज्यों से लोग आकर यहां के लोगों का शोषण करें। पहले झारखंडियों को उनका पूरा हक और अधिकार मिलेगा, उसके बाद ही दूसरे राज्यों के लोगों के बारे में विचार किया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की आंतरिक परिस्थितियों और यहां के लोगों की समस्याओं को राज्य के लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। गांव, देहात, सुदूरवर्ती इलाकों और शहरों में रहने वाले सभी लोगों को राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने नई पीढ़ी से सोबरन मांझी और झारखंड आंदोलन के तमाम शहीदों के संघर्ष को याद रखने तथा आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की।

खूंटी के 300 गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य, 100 दिवसीय अभियान शुरू

नई सोच एक्सप्रेस



खूंटी। अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समाहरणालय में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर 100 दिवसीय अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई और जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक में अभियान के तहत जिले के 300 गांवों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का प्रस्ताव पारित कराने, किशोर-किशोरियों और महिला समूहों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित करने तथा जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया। साथ ही ग्राम बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने की योजना बनाई गई। उपायुक्त ने बाल विवाह और बाल तस्करी के जोखिम वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता संदेश प्रसारित करने के साथ बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया। महिला सशक्तीकरण और विद्यालय छोड़ चुके बच्चों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। इस अभियान की सफलता के लिए जागरूकता के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। बैठक में सिविल सर्जन, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बेटी की हत्या मामले में माता- पिता गिरफ्तार

नई सोच एक्सप्रेस



पूर्वी सिंहभूम। कमलापुर थाना पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में माता-पिता को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार पिता रवींद्र मुर्मू और मां सुमानी मुर्मू को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।पुलिस जांच में सामने आया है कि मोबाइल फोन चलाने की आदत को लेकर मां-बेटी के बीच हुए विवाद के बाद दंपति ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।कमलपुर थाना प्रभारी धनंजय पासवान ने शुक्रवार को बताया कि कनकलता को लगातार मोबाइल फोन चलाने की आदत थी। इसी बात को लेकर 10 नवंबर को उसका अपनी मां से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान गुस्से में आकर माता-पिता ने घर में ही डंडे से उसकी पिटाई कर दी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण कनकलता की मौत हो गई। इसके बाद घटना को छिपाने और साक्ष्य मिटाने की नीयत से दोनों ने देर रात बेटी के शव को लायाडीह के पास महीनों से बंद पड़ी पत्थर खदान के गहरे पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने बेटी के लापता होने की कहानी भी बनाई, ताकि किसी को उन पर संदेह न हो।इस मामले में 13 नवंबर को ओड़िया पंचायत के लायाडीह गांव स्थित बंद पत्थर खदान से कनकलता का शव बरामद किया गया था।वह गेरुवाला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा थी। शव मिलने के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया था। ग्रामीणों ने खदान के गड्ढों को भरने, खदान मालिक को मौके पर बुलाने और मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की थी।इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। थाना प्रभारी धनंजय पासवान ने बताया कि शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान परिजनों के व्यवहार और परिस्थितियों को देखते हुए संदेह गहराया। पुलिस ने करीब दस दिनों तक लगातार छानबीन की और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के साथ कई लोगों से पूछताछ की। इसके बाद माता-पिता से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि घटना के विरोध में 14 नवंबर को ग्रामीणों ने टाटा-काटिन मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने पुलिस पर शव को चोरी-छिपे ले जाने का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और घटना में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

नवजात के मासूम की मौत से मचा हड़कंप, एएनएम पर गलत टीका लगाने का आरोप

कोडरमा। जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के माथाडीह वार्ड नंबर तीन में 36 दिन के नवजात की मौत के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र की एएनएम रिंकी देवी पर निर्धारित उम्र से पहले गलत टीका लगाने का गंभीर आरोप लगाते हुए शहीद चौक पर नवजात का शव सड़क पर रखकर कोडरमा-गिरिडीह मुख्य मार्ग जाम कर दिया।इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया। परिजनों के अनुसार, गुरुवार को माथाडीह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण अभियान चल रहा था, जहां बच्चे की मां रूपा देवी को भी बुलाया गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बच्चे की उम्र कम होने का हवाला देते हुए टीका लगाने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद एएनएम ने उसे चार टीके लगा दिए। परिजनों का दावा है कि 45 दिन की उम्र में दिए जाने वाले टीके 36 दिन के बच्चे को लगा दिए गए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और शुक्रवार तड़के उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चा पप्पू कुमार का इकलौता पुत्र था। उसे पहले से दो पुत्री भी है। मासूम की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने संबंधित एएनएम को बर्खास्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची डोमचांच पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। हालांकि, टीकाकरण में कथित लापरवाही और बच्चे की मौत के बीच संबंध की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकेगा।

किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने का उपायुक्त ने दिया निर्देश

खूंटी।किसानों को खेती के लिए समय पर बीज उपलब्ध कराने को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बीज विनिमय वितरण कार्यक्रम और बीज उत्पादन से संबंधित बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिले के सभी लैम्प्स केंद्रों के माध्यम से किसानों को ससमय बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी लैम्प्स अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित लैम्प्स केंद्रों से गेहूं, चना, मसूर, सरसों सहित अन्य फसलों के बीज का वितरण निर्धारित समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं हो और उन्हें अपने नजदीकी लैम्प्स केंद्रों पर आसानी से बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।बैठक में प्रखंड स्तर पर कृषि कार्यों के संचालन और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समन्वय पर भी बल दिया गया। उपायुक्त ने सभी एटीएम (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजर) एवं बीटीएम (ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर) को टीम भावना के साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा, सभी लैम्प्स अध्यक्ष, एटीएम, बीटीएम सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

चाईबासा मंडल कारा में 11 टीमों ने की सघन तलाशी



पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस ने गुरुवार देर रात चाईबासा मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू के संयुक्त नेतृत्व में हुए इस अभियान का उद्देश्य जेल की आंतरिक सुरक्षा, बंदियों को मिल रही सुविधाओं और कारा प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लेना था।निरीक्षण के लिए कुल 11 जांच दल गठित किए गए थे। इनमें प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे। सभी दलों ने अपने निर्धारित क्षेत्रों में एक साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान बंदियों के विभिन्न वार्डों और बैरकों, भोजनालय, जेल अस्पताल, शौचालय तथा अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से पड़ताल की गई। अधिकारियों ने बंदियों के रहने की स्थिति, परिसर की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जांच की गई।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उनसे भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूछताछ की गई। कारा प्रशासन को निर्देश दिया गया कि बंदियों को सभी निर्धारित बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।सघन तलाशी के बावजूद जेल परिसर और बंदी वार्डों से कोई आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने और संभावित लापरवाही की गुंजाइश खत्म करने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

रबी कार्यशाला में किसानों को दी गई आधुनिक खेती की जानकारी

नई सोच एक्सप्रेस



पलामू। कृषि विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को मेदिनीनगर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला सह 'खेत बचाओ अभियान' का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त सादात अनवर एवं जिला कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी गई।कृषि वैज्ञानिकों ने रबी मौसम की प्रमुख फसलों गेहूं, चना, मसूर, सरसों और मक्का की उन्नत खेती के तरीकों से किसानों को अवगत कराया। इस दौरान बीजोपचार, प्राकृतिक खेती, हरी खाद, संतुलित उर्वरक के उपयोग और कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर जोर दिया गया।कार्यशाला के दौरान विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच सरसों बीज, स्वीकृति पत्र सिहत अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके तहत 10 प्रगतिशील किसानों को उन्नत प्रभेद का सरसों बीज, दो किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना और एक किसान को किसान समृद्धि योजना का लाभ दिया गया।वहीं एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया। कार्यशाला के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती अपनाकर उत्पादन बढ़ाने एवं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया।

भारत माला और बेड़ो-खूंटी बाइपास सड़क परियोजना के विरोध में ग्रामीणों की बैठक



नई सोच एक्सप्रेस

खूंटी। भारत माला सड़क परियोजना और बेड़ो-खूंटी बाइपास सड़क के विरोध में शुक्रवार को हाई स्कूल मैदान में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता फ्रिंनकेलन धान ने की। इसमें जल, जंगल, जमीन आंदोलन के संयोजक अलेस्टर बोदरा मुख्य रूप से उपस्थित थे।बैठक के दौरान अलेस्टर बोदरा ने कहा कि ग्रामसभा और जमीन मालिकों की सहमति के बिना पूर्वजों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत माला सड़क परियोजना बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सड़क स्थानीय लोगों की जमीन से होकर गुजरेगी, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार और अधिकारियों पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने तथा खनिज संपदा के दोहन का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे फ्रिंनकेलन धान ने बेड़ो-खूंटी बाइपास सड़क परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि ग्रामीणों की पैतृक जमीन और अधिकारों की अनदेखी कर जमीन अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में परियोजनाओं के विरोध में 29 जनवरी 2027 को जनसभा और रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पतरस होरो, आनंद होरो, सनिका धान, गोविंदा कच्छप, फागु होरो सहित दर्जनों महिला-पुरुष उपस्थित थे।

अग्रसेन पब्लिक स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह 'विबग्योर' की रंगारंग छटा, मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित

नई सोच एक्सप्रेस



कुरुक्षेत्र।अग्रसेन पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 'विबग्योर' हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। समारोह में नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान कक्षा पहली से पांचवीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र के एचसीएस एवं अतिरिक्त उपायुक्त तथा केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार सेतिया उपस्थित रहे। स्कूल अध्यक्ष नितिन गोयल, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल समिति के चेयरमैन केसी अग्रवाल, संस्थापक सदस्यों, प्रबंधन समिति के सदस्यों और प्रधानाचार्या रीटा गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। स्कूल बैंड की मधुर धुनों और एनसीसी कैडेट्स की शानदार परेड ने समारोह की शुरुआत को आकर्षक बना दिया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। पहली कक्षा के बच्चों ने बालमन की मासूमियत को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया, जबकि दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दीं। तीसरी कक्षा के बच्चों ने विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का संदेश दिया। वहीं, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों ने पंचतत्व पर आधारित प्रस्तुति के जरिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के महत्व के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के भांगड़ा और गिद्दा ने समारोह में विशेष रंग भर दिया। स्कूल अध्यक्ष नितिन गोयल ने अपने संबोधन में संस्थान की उपलब्धियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानाचार्या रीटा गोयल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और विभिन्न गतिविधियों में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मुख्य अतिथि पंकज कुमार सेतिया ने बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर विद्यार्थी जीवन की हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद कक्षा पहली से पांचवीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक एवं प्रबंधन समिति के सदस्य ईश्वर चंद सिंगला, राजेंद्र सिंघल, राजेश अग्रवाल, मानिक गोयल, अमित गोयल, रोशन लाल गुप्ता, जय भगवान सिंगला और मयंक गर्ग सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। अंत में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ समारोह का समापन हुआ।

सिकंदरा में विधानसभा स्तरीय निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित



नई सोच एक्सप्रेस

सिकंदरा। मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी कार्यक्रम के तहत निर्वाचक साक्षरता क्लब की ओर से शुक्रवार को सिकंदरा प्रखंड कार्यालय सभागार में 240 सिकंदरा विधानसभा स्तरीय निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रखंड के विभिन्न उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से चयनित छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का नेतृत्व विधानसभा स्तरीय ईएलसी रूपम कुमारी एवं समन्वयक मनीष कुमार पाठक ने किया। निबंध प्रतियोगिता का विषय 'शुद्ध मतदाता सूची का महत्व एवं मतदान का महत्व' था। वहीं क्विज प्रतियोगिता लिखित एमसीक्यू प्रारूप में आयोजित हुई, जिसमें मतदाता सूची निर्माण, ईवीएम, वीवीपैट, मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न पूछे गए। निबंध प्रतियोगिता में झाडो सिंह प्लस टू उच्च विद्यालय, लछुआड़ के सौरभ कुमार तथा प्लस टू उच्च विद्यालय, सिकंदरा के ऋषु राज चयनित हुए। वहीं क्विज प्रतियोगिता में प्लस टू उच्च विद्यालय, धधाड़ की सिंपी कुमारी एवं परियोजना उच्च विद्यालय, सिकंदरा की मेहर खातून ने सफलता हासिल की। चयनित चारों विद्यार्थी अब 1 दिसंबर 2026 को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, ईएलसी समन्वयक एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

पूर्वांचल भवन में 28 एवं 29 नवंबर को होगा चतुर्थ अखण्ड अष्ट्याम का भव्य आयोजन

नई सोच एक्सप्रेस



गुरुग्राम।पूर्वांचल जन कल्याण संघ, मारुति कुंज (रजि.) के तत्वावधान में पूर्वांचल भवन, वाटिका कुंज, मारुति कुंज में 28 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक चतुर्थ अखण्ड अष्ट्याम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने समाजसेवी इं. आर. के. जायसवाल से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अखण्ड अष्ट्याम का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय धार्मिक आयोजन में अखण्ड कीर्तन एवं भजन-कीर्तन के साथ-साथ पूर्वांचल के प्रसिद्ध भोजपुरी गायक एवं गायिकाएं भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन में मारुति कुंज एवं आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों सहित अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। पिछले कई हफ्तों से संस्था के सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय लोगों के डोर-टु-डोर पहुंचकर जानकारी के साथ आमंत्रण दिया जा रहा। अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने सभी क्षेत्रवासियों एवं पूर्वांचल समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार, पड़ोसियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ इस धार्मिक आयोजन में सपरिवार शामिल हों तथा अखण्ड अष्ट्याम में भाग लेकर पुण्य के भागी बनें। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

काशी की साहित्यिक धरोहर को नई धार हिंदी संस्थान में डॉ.गीता शास्त्री के मनोनयन पर गुलाब बाग कार्यालय में स्वागत

नई सोच एक्सप्रेस



वाराणसी।उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेत्री डॉ.गीता शास्त्री के मनोनयन पर काशी और भाजपा महानगर में हर्ष की लहर दौड़ गई | इस अवसर पर शुक्रवार को गुलाब बाग स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया इस नियुक्ति को साहित्य,संस्कृति और संगठन के सार्थक संगम के रूप में देखा जा रहा है | डॉ.गीता शास्त्री की इस उपलब्धि पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया | उन्होंने कहा कि डॉ.शास्त्री का हिंदी संस्थान से जुड़ना न केवल भाजपा परिवार के लिए गौरव का विषय है बल्कि इससे काशी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को भी नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी | महानगर अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि उनके दीर्घ अनुभव, बौद्धिक समृद्धि और दूरदर्शिता से हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को नई गति मिलेगी तथा नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ने का सशक्त मंच और प्रोत्साहन प्राप्त होगा | महानगर के अनेक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डॉ.गीता शास्त्री को पुष्पगुच्छ व बधाई देकर उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं | स्वागत करने वाले अन्य प्रमुख लोगों में महानगर मीडिया संयोजक प्रमील पाण्डेय, चंद्रशेखर उपाध्याय,पूजा दीक्षित, अजय गुप्ता,अखिलेंद्र सिंह सन्नी, अमित खरे,सपना सिंह,प्रज्ञा पाण्डेय,नेहा कक्कड़,हीरा यादव, राजेंद्र शंकर सिंह पटेल,मनोज तिवारी,योगेश वर्मा,मिलन केशरी आदि रहे ||



मार्गशीर्ष में इन 3 चीजों का दान माना जाता है शुभ

मार्गशीर्ष का महीना में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है. इस महीने में दान-पुण्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इस महीने में जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लोगों को खासतौर पर चावल, गुड़ और तिल का दान करना चाहिए.
मान्यता है कि इस महीने में दान-पुण्य से जीवन में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है. आइए जानते है की मार्गशीर्ष के महीने में क्या दल करे और चावल, गुड़ और तिल का विशेष महत्व क्यों हैं.

चावल दान का क्या महत्व है

चावल या अक्षत का हिन्दू धर्म में विशेष महत्व हैं, पूजा-पाठ में चावल का इस्तेमाल करना शुभ होता है. चावल को अन्न का प्रतीक माना जाता है. इसलिए मार्गशीर्ष के महीने में चावल का दान करना अच्छा माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में किसी जरूरतमंद को चावल या भोजन देने से पुण्य मिलता है. इससे अन्न का सम्मान करने और दूसरों की मदद करने का संदेश भी मिलता है.

गुड़ दान का क्या महत्व है

गुड़ का इस्तेमाल पूजा-पाठ और कई शुभ कामों में किया जाता है. इसे मिठास और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. सर्दियों में गुड़ खाने की परंपरा भी काफी पुरानी है. मार्गशीर्ष के महीने में गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और खुशहाली बनी रहती है. इस महीने में गरीबों और जरूरतमंदों को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें दान की जा सकती हैं.

तिल दान का क्या महत्व है

हिंदू धर्म में तिल को बहुत पवित्र माना गया है. पूजा-पाठ, हवन और पितरों के तर्पण में तिल का इस्तेमाल किया जाता है. खासतौर पर काले तिल का प्रयोग पितरों से जुड़े धार्मिक कामों में होता है. मार्गशीर्ष के महीने में तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि तिल का दान करने से पुण्य मिलता है. सर्दियों में तिल के लड्डू और दूसरी चीजें बनाकर खाने और बांटने की भी परंपरा है.

कैसे करें चावल, गुड़ और तिल का दान

मार्गशीर्ष के महीने में अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार चावल, गुड़ और तिल का दान कर सकते हैं. इन चीजों को किसी जरूरतमंद परिवार, गरीब व्यक्ति या मंदिर के अन्नदान में दे सकते हैं. चाहें तो इन तीनों चीजों को मिलाकर खाने-पीने की सामग्री के रूप में भी दान कर सकते हैं. दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी की जरूरत पूरी हो सके. धार्मिक मान्यताओं में दान का सबसे बड़ा महत्व दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना बताया गया है.





1 दिसंबर को भैरव अष्टमी, शिव के गुस्से से जन्मे काल भैरव के काशी में बसने की कहानी

मृत्यु और समय के स्वामी हैं काल भैरव. वे भगवान शिव के अंश भी है. उनकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी, इस वजह से हर साल इस तिथि को काल भैरव जयंती मनाते हैं. हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी मनाते हैं, जो काल भैरव को स?मर्पित है. काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग, दोष, तंत्र-मंत्र के दुष्प्रभाव, नकारात्मकता आदि दूर होते हैं. काल भैरव जयंती के लिए निशिता मुहूर्त का विचार करते हैं, न कि उदयातिथि का.

काल भैरव जयंती 1 दिसंबर 2026 को मनाई जाएगी, जब भगवान शिव ने ब्रह्मा के घमंड को तोड़ने के लिए काल भैरव को प्रकट किया था। इस दिन पूजा करने से भय, बाधाएं दूर होती हैं और सुख-शांति मिलती है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय परंपराएं भी निभाई जाती हैं।
हिंदू धर्म में अनेक पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से एक कथा भगवान ब्रह्मा और शिव के भैरव रूप से जुड़ी है। बताया जाता है कि, जब ब्रह्मा के पांचवें सिर को शिव से श्रेष्ठ होने का घमंड था, तब भगवान शिव ने अपने गुस्से और तेज से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने अपने अंगूठे के नाखून से ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया। ब्रह्महत्या पाप के कारण उनका पांचवां सिर भैरव बाबा के हाथ में चिपक गया और काशी पहुंचने पर सिर नीचे गिर गया, उस स्थान को अब



कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। उस दिन से काल भैरव (काशी के कोतवाल) के तौर पर वहां रहते हैं। हिंदू धर्म में काल भैरव की जयंती का खास महत्व है। काल भैरव जयंती इस साल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 1 दिसंबर को मध्य रात्रि 12 बजकर 11 मिनट से शुरू हो रही है। यह तिथि 1 दिसंबर को ही रात 11 बजकर 12 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। उदयातिथि के आधार पर अष्टमी तिथि 1 दिसंबर को मनाई जानी है और उसी दिन निशिता मुहूर्त में पूजा होगी।

काल भैरव जयंती शुभ मुहूर्त

काल भैरव जयंती के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 8 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 2 मिनट तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में नहाकर काल भैरव जयंती के लिए पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दिन में 11 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है। वहीं निशिता मुहूर्त देर रात 11 बजकर 43 मिनट से लेकर 12 बजकर 38 मिनट तक है।

काल भैरव जयंती का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से जीवन में डर, परेशानियों और बाधाओं से छुटकारा मिलता है। भक्त अपने जीवन में सुख-शांति, तरक्की औ सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इसके अलावा इस दिन काल भैरव अष्टकम का पाठ करने के साथ सरसों के तेल का दीया जलाने और कुत्तों को खाना खिलाने से काल भैरव खुश होते हैं। इस दिन को भैरव अष्टमी और कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने कालाष्टमी प्रत्येक महीने की अष्टमी तिथि को पड़ती है।

काल भैरव जयंती पर अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराएं

वाराणसी- काल भैरव जयंती पर भैरव मंदिर में संपूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया जाता है, जिसे चांदी की खोपड़ियों की माला से सजाया जाता है। कई लोग शहर के आठ भैरव मंदिरों के दर्शन करते हैं।
उज्जैन- काल भैरव मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिलती है और खास तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
कर्नाटक और तमिलनाडु- भैरव और शिव मंदिरों में अभिषेक करने के साथ रात के समय पूजा की जाती है।
नेपाल- काठमांडू घाटी में कई मंदिरों में भी शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है।



काल भैरव जयंती पर क्यों की जाती है काले कुत्ते की सेवा?

काल भैरव जयंती 1 दिसंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. इस दिन काल भैरव की खास पूजा होती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से काल भैरव की पूजा करने से भय, नकारात्मकता और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. इस दिन पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान के साथ काले कुत्ते की सेवा करना चाहिए.
मान्यता है कि काले कुत्ते को भोजन कराने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना जाता है. उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है. धार्मिक चित्रों और मूर्तियों में भगवान काल भैरव को कुत्ते पर सवार दिखाया जाता है. इसी वजह से कुत्ते को उनका वाहन माना गया है.
विशेष रूप से काले कुत्ते को काल भैरव से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते की सेवा करने से भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
काल भैरव की पौराणिक कथा शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में भगवान भैरव के प्राकट्य से जुड़ी कथा मिलती है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ. इस दौरान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहीं. इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके तेज से काल भैरव प्रकट हुए. काल भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मस्तक को अलग कर दिया. इसके बाद उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीर्थाटन करना पड़ा. अंत में काशी पहुंचने पर उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली. इसी कारण काशी में भगवान काल भैरव को नगर का रक्षक माना जाता है.

काले कुत्ते को रोटी खिलाने की क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, काल भैरव को कुत्ता प्रिय है. इसलिए उनकी पूजा में काले कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को रोटी या अन्य उपयुक्त भोजन खिलाने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं. ज्योतिषीय शास्त्र की मान्यता के अनुसार, कुत्ते को भोजन कराने से शनि और राहु से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं.

काल भैरव जयंती पर कैसे करें कुत्ते की सेवा?

काल भैरव जयंती के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान काल भैरव की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें. इसके बाद किसी बेसहारा या जरूरतमंद कुत्ते को भोजन करा सकते हैं. पशुओं को भोजन देते समय उनकी सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए. उन्हें जबरदस्ती कुछ न खिलाएं.

अपने प्रिय भगवान को उनकी पसंद का फूल चढ़ाएं

भारतीय संस्कृति में पुष्प यानी फूल का विशेष महत्व है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ में भगवान को फूल अर्पित करना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। फूलों को लेकर संस्कृत में एक वाक्य भी है दैवस्य मस्तकं कुर्यात्कुसुमोपहितं सदा। अर्थात भगवान का मस्तक महेशा पुष्प (फूल) से सुशोभित रखना चाहिए।

भगवान विष्णु का पसंदीदा फूल

इस लेख में सबसे पहले भगवान विष्णु के बारे में जिक्र करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फूल कदंब का फूल है। कहा जाता है कि इस फूल को चढ़ाने से विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और घर में धन की वर्षा भी होती है। कदंब के फूल के अलावा चेमली, चंपा, केवड़ा और कमल को भी भगवान विष्णु का प्रिय फूल माना जाता है।

भगवान शिव का प्रिय फूल

यह तो सब जानते हैं कि भगवान शिव का प्रिय फूल बेल का पत्ता और धतूरा फूल हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव शमी के फूल और पत्ते भी बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा हरसिंगार का फूल, नाग केसर का फूल और कनेर का फूल भी भगवान शिव बहुत पसंद करते हैं।

भगवान कृष्ण का प्रिय फूल

कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रिय फूलों का जिक्र महाभारत में भी है। जी हां, परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण कुमुद, करवरी, पलाश और वनमाला बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा कृष्ण कमल भी कृष्ण जी को बहुत पसंद हैं।

भगवान गणेश का प्रिय फूल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी लाल फूल को बहुत पसंद करते हैं। यह मान्यता है कि वो दूर्वा सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा गुड़हल और लाल गुलाब भी बहुत पसंद करते हैं। गेंदा का फूल भी भगवान गणेश बहुत पसंद करते हैं।

हनुमान जी का प्रिय फूल

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। इसलिए कई लोग हनुमान जी का पूजा करते वक्त लाल गुलाल भी चढ़ाते हैं। उन्हें लाल गेंदा और लाल गुलाब चढ़ाना शुभ माना जाता है।

शनिदेव का प्रिय फूल

यह मान्यता है कि शनिदेव नीले रंग का फूल बहुत पसंद करते हैं। इसलिए कई लोग शनिदेव पर नीले लाजवन्ती का फूल चढ़ाते हैं। लाजवन्ती के अलावा अन्य नीले रंग के फूल को भी शनिदेव बहुत पसंद करते हैं।
इसके अलावा मां लक्ष्मी का प्रिय फूल कमल माना जाता है। मां दुर्गा लाल गुलाब या लाल लाल गुड़हल बहुत पसंद करती हैं।



मार्गशीर्ष मास के दौरान क्या करें और क्या न करें



मार्गशीर्ष मास श्रीहरि और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत विशेष माना जाता है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है जिसे अगहन मास भी कहते हैं। इसी माह में खरमास भी लगने जा रहा है। ऐसे में इस महीने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास का आरंभ होता है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान विष्णु और प्रभु श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। इस दौरान स्नान, दान, जप और गीता का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही, इस दौरान महत्वपूर्ण नियमों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसी बीच खरमास भी शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में भूलकर भी कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए और कुछ कार्यों को करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है।
25 नवंबर, बुधवार से मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो गई है। वहीं, 23 दिसंबर, बुधवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इसका समापन होगा। ऐसी मान्यता है कि यह मास भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस दौरान श्रद्धाभाव के साथ श्रीकृष्ण की पूजा करने का अत्यधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए।

मार्गशीर्ष मास में भूलकर भी न करें ये काम

तामसिक भोजन का सेवन : भूलकर भी मार्गशीर्ष मास में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।
कटु वाणी का प्रयोग : कभी भी असहाय और अपने से बड़े-बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही, इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें हैं और घर-परिवार में कटु वाणी का प्रयोग करने से बचें।
खरमास का रखें ख्याल : इस साल 16 दिसंबर, बुधवार से सूर्य धनु राशि में रहेंगे और खरमास मकर संक्रांति 14 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए 16 दिसंबर से मांगलिक और गृह प्रवेश जैसे कार्यों से बचें।
एकादशी व्रत के नियम : मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी तिथियों पर नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो, तो कठिन उपवास न करें। इसके स्थान पर आप अपनी क्षमता के अनुसार पूजा कर सकते हैं।

मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए

सूर्य को दें अर्घ्य : मार्गशीर्ष मास में कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे में प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करें। इस दौरान 'ओम सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें।
श्रीहरि और भगवान कृष्ण की पूजा : पूजा घर अच्छी तरह साफ करने के बाद भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इसके बाद, मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही, 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें।
भगवत गीता करें पाठ : गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम।' नियमित रूप से प्रतिदिन एक अध्याय या कुछ श्लोक का पाठ अवश्य करें।
दान करें : मार्गशीर्ष मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में इस दौरान आप जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या सर्दी के इस मौसम में कंबल का दान अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं।
तुलसी पूजन और दीपदान : हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का बहुत खास महत्व होता है। ऐसे में प्रतिदिन सुबह और शाम के समय तुलसी की पूजा जरूर करें। साथ ही, शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है।

मिमी चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ दत्ता से की सगाई और कोर्ट मैरिज, 5 दिसंबर को कलिम्पोंग में लेंगे सात फेरे



बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने लंबे समय के प्रेमी सिद्धार्थ दत्ता के साथ 26 नवंबर 2026 को कोलकाता में गुपचुप तरीके से सगाई और कोर्ट मैरिज कर ली है, जिससे उनके प्रशंसकों को सुखद आश्चर्य हुआ। इस खास मौके की तस्वीरें मिमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कीं, हालांकि उन्होंने बड़ी ही सावधानी से अपने जीवनसाथी सिद्धार्थ का चेहरा छिपाकर रखा, जिससे प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई। समारोह कोलकाता के कस्बा स्थित मिमी के घर पर बेहद सादगी से आयोजित किया गया, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। नवविवाहित जोड़े ने आइवरी रंग के पारंपरिक परिधान पहने थे; मिमी ने सुनहरी कढ़ाई वाला आइवरी परिधान चुना, जबकि सिद्धार्थ भी आइवरी शेरवानी में नजर आए। सिद्धार्थ दत्ता मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और फिल्म उद्योग की चकाचौंध से हमेशा दूर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा और सीधे शादी का फैसला लिया। कानूनी तौर पर शादी के बंधन में बंधने के बाद, अब यह जोड़ा पारंपरिक रीति-रिवाजों से सात फेरे लेने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार, मुख्य विवाह समारोह पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पहाड़ी इलाके कलिम्पोंग में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। 3 दिसंबर को कॉकटेल और डिनर पार्टी के साथ प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू होंगे। 4 दिसंबर को मेहंदी और संगीत की रस्में निभाई जाएंगी, और 5 दिसंबर को कपल पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधेगा। कलिम्पोंग से लौटने के बाद, 11 दिसंबर को कोलकाता में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी दी जाएगी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। मिमी चक्रवर्ती बंगाली मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो गानेर ओपारे से की थी और कई सुपरहिट बंगाली फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। एक्टिंग के अलावा, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर सीट से सांसद चुनी गईं, हालांकि फरवरी 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। कोलकाता में बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज और सगाई की रस्में पूरी करने के बाद अब अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और सिद्धार्थ दत्ता पारंपरिक विवाह समारोह की तैयारियों में जुट गए हैं। कानूनी तौर पर एक-दूसरे का हाथ थामने के बाद यह जोड़ा अब पश्चिम बंगाल की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में सात फेरे लेगा। जानकारी के अनुसार, विवाह के मुख्य पारंपरिक आयोजन कलिम्पोंग में रखे गए हैं, जहाँ परिवार और चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में शाही अंदाज में रस्में निभाई जाएंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक, कलिम्पोंग में प्री-वेडिंग उत्सव की शुरुआत 3 दिसंबर को कॉकटेल और डिनर पार्टी के साथ होगी। इसके अगले दिन यानी 4 दिसंबर को मेहंदी और संगीत की रंगारंग शाम सजेगी, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य शामिल होंगे। मुख्य विवाह समारोह 5 दिसंबर को होगा, जब मिमी और सिद्धार्थ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। पहाड़ों में शादी संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़ा कोलकाता लौटेगा और 11 दिसंबर को एक भव्य रिसेप्शन पार्टी की मेजबानी करेगा। इस समारोह में बंगाली फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों, राजनीतिक हस्तियों और करीबी मित्रों के शामिल होने की उम्मीद है।

तनिषा ने की रामायण : पार्ट 1 में रणबीर के अभिनय की खूब तारीफ



कई दर्शकों ने शुरुआत में अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म रामायणः पार्ट 1 में भगवान राम के किरदार के लिए सही विकल्प नहीं माना था, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनकी राय बदल गई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायणः पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लेकर हाल ही में, अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर और यश के अभिनय की जमकर तारीफ की, लेकिन सीता के किरदार में साई पल्लवी को लेकर निराशा व्यक्त की। तनिषा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रामायण का रिव्यू लिखते हुए कहा कि मीडिया अक्सर गुमराह करने वाला होता है, और यह पूरी तरह से राम की फिल्म है। उन्होंने रणबीर कपूर के अभिनय को लाजवाब बताया और कहा कि एनिमल में उन्हें देखने के बाद उन्हें लगा था कि वे रणबीर को भगवान राम के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगी, लेकिन रणबीर ने इस किरदार को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाया है। सीता के रूप में साई पल्लवी को मिसकास्ट बताते हुए तनिषा ने लिखा कि वे मानती हैं कि साई पल्लवी एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन सीता के किरदार में वे उन्हें सही नहीं लगीं, जिसके कारण वे फिल्म से पूरी तरह जुड़ नहीं पाईं। हालांकि, उन्होंने फिल्म के बाकी विजुअल्स और अन्य कलाकारों के अभिनय को शानदार बताया। यश ने रावण के किरदार में कमाल किया है और अपनी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने किरदार को बखूबी निभाया है। तनिषा के अनुसार, राम और रावण, दोनों के किरदारों को अभिनेताओं ने शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा है, जिसमें रावण, राम को कड़ी टक्कर देता नजर आता है। उन्होंने दर्शकों को यह फिल्म देखने की सलाह दी है।

रामायण में साई पल्लवी को सीता के किरदार के लिए चुने जाने पर फिल्म रिलीज से पहले और बाद में भी खूब बहस हुई। कुछ लोगों ने उनके चुनाव की सराहना की, जबकि कुछ ने महसूस किया कि इस भूमिका के लिए अन्य अभिनेत्रियां बेहतर हो सकती थीं। कुछ दर्शकों को फिल्म में सीता को एक योद्धा के रूप में दिखाना पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। इस विवाद के बीच, साई पल्लवी की नई फिल्म ओम थिएटर्स में रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ धनुष नजर आ रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान धनुष ने साई पल्लवी का पक्ष लेते हुए कहा था कि सीता के किरदार को लेकर इतना शोर क्यों मचा है, यह उन्हें समझ नहीं आता। उन्होंने साई पल्लवी की गहरी श्रद्धा, साफ दिल, सुंदरता और बेहतरीन अभिनय की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे बेहतर सीता नहीं मिल सकती। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश और रवि दुबे के अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

ट्विंकल ने अक्षय कुमार को करण के शो में मुफ्त में जाने पर कही ये बात



कॉफी विद करण 9 में अक्षय कुमार खास मेहमान बनकर शामिल हुए। इस दौरान शो के कॉल अ स्टार सेगमेंट में करण जौहर ने अक्षय से उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन करने के लिए कहा। दोनों के बीच हुई बेबाक बातचीत ने अब सबका ध्यान खींचा है। दरअसल, ट्विंकल ने करण के चैट शो में मुफ्त में शामिल होने को लेकर अक्षय पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा। अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल को फोन लगाया। बातचीत के दौरान, ट्विंकल ने बताया कि वह अक्षय के शो में आने के बारे में पहले ही करण से बात कर चुकी थीं। उन्होंने अपने पति से कहा, मेरी कल ही करण से बात हुई थी। फिर उन्होंने आगे कहा, उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आज इसमें शामिल हो रहे हो। हालांकि, ट्विंकल की अगली बात ने बातचीत को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और शो के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने कहा, आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है। करण ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए? इस पर ट्विंकल चौंककर बोलीं, अरे, वो भी सुन रहे हैं। करण ने इसके बाद मजाक में उनसे पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि कॉफी विद करण में आने के लिए मुझे आपके पति को पैसे देने चाहिए? उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह बातचीत शो के एपिसोड में शामिल होगी, उन्होंने ट्विंकल से कहा कि वह अभी ऑन एयर हैं और वह इस बातचीत को शो से नहीं हटाएंगे। अब ट्विंकल की इस बात को सुनकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी अक्सर अपने बेबाक अंदाज, हाजिरजवाबी और हल्के-फुल्के मजाक के लिए जानी जाती है। दोनों ही अपने विचारों को बिना किसी बनावट के रखने के लिए पहचाने जाते हैं, यही वजह है कि जब भी उनसे जुड़े किसी किस्से या बातचीत का जिक्र आता है, तो उसमें एक स्वाभाविक ताजगी देखने को मिलती है। सार्वजनिक मंच हो या निजी बातचीत, दोनों के बीच की सहजता और बेफिक्री दर्शकों को हमेशा खास लगती है। मनोरंजन जगत में सेलिब्रिटी चैट शोज की एक बड़ी खासियत यह होती है कि इनमें सितारे कई बार स्क्रिप्टेड जवाबों से हटकर बेहद सहज और अनौपचारिक अंदाज में नजर आते हैं। खासतौर पर जब परिवार के किसी करीबी सदस्य से फोन पर बात जुड़ जाए, तो माहौल और भी हल्का व दिलचस्प हो जाता है। ऐसे पलों में होने वाली नोकझोंक और मजेदार टिप्पणियाँ कई बार शो के सबसे चर्चित हिस्सों में बदल जाती हैं, क्योंकि इनमें दिखावे के बजाय असली बॉन्डिंग झलकती है। अक्षय कुमार अपनी व्यस्त दिनचर्या, अनुशासन और काम की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, वहीं ट्विंकल खन्ना अपने तीखे लेकिन मजेदार व्यंग्य और स्पष्टवादिता के लिए अलग पहचान रखती हैं। जब इन दोनों का अंदाज एक साथ आता है, तो सामान्य-सी बात भी चर्चा का विषय बन जाती है। दर्शक भी ऐसे पलों को गंभीरता से कम और मनोरंजन के तौर पर ज्यादा देखते हैं, जहाँ सितारों के बीच की दोस्ती और सहजता खुलकर सामने आती है। कुल मिलाकर, सेलिब्रिटी के बीच होने वाली ऐसी हल्की-फुल्की बातचीत चैट शोज को एक अलग ही ऊर्जा देती है। यह दिखाती है कि व्यस्त और ग्लैमरस दुनिया के बीच भी रिश्तों में वही पुरानी बेफिक्री और हंसी-मजाक कायम है, जो लोगों को इन सितारों से और करीब से जोड़ता है।

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका से दक्षिण सिनेमा में डेब्यू करेंगे गोविंदा

एटली की आगामी साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म राका को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा भी इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में गोविंदा की दिखाई देने की कुल अवधि भले ही कम हो, लेकिन कहानी में उनका किरदार काफी अहम होगा। सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में इस कास्टिंग का जिक्र किया गया है। हालांकि, न तो फिल्म के निर्माताओं, न ही गोविंदा और न ही उनकी टीम ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की है। उनके किरदार को लेकर भी फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। अगर यह खबर सही साबित होती है, तो यह दक्षिण भारतीय सिनेमा में गोविंदा की पहली फिल्म होगी। एटली राका का निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आ सकते हैं। अल्लू और दीपिका के अलावा, मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना के भी इस फिल्म का हिस्सा होने की चर्चा है। खबर है कि राम्या कृष्णन, योगी बाबू और जिम सर्भ को भी अहम किरदारों के लिए चुना गया है। फिल्म की कहानी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।

सनी देओल और अक्षय खन्ना की दमदार कोर्टरूम ड्रामा फ़िल्म 'इक्का' का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर रविवार, 29 नवंबर को सिर्फ़ ज़ी सिनेमा पर



जब इंसाफ की लड़ाई निजी जंग बन जाए और अतीत के दबे हुए राज सामने आने लगें, तो अदालत ही उस जंग का सबसे बड़ा मैदान बन जाती है। सही और गलत के बीच की कशमकश, रिश्तों की उलझनें और अचानक होने वाले टकराव से भरी ऐसी ही कहानी लेकर आ रहा है ज़ी सिनेमा। सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'इक्का' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर रविवार, 29 नवंबर को रात 8 बजे होगा। सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा द्वारा निर्देशित और अल्केमी फ़िल्म्स द्वारा निर्मित इक्का लगभग तीन दशकों बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ लेकर आई है। बॉर्डर में अपनी यादगार साझेदारी के बाद दोनों दिग्गज कलाकार इस फिल्म में एक बार फिर आमने-सामने नजर आते हैं। अदालत की तीव्र पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म न्याय और व्यक्तिगत विश्वास के बीच की महीन रेखा को तलाशती है और एक अहम सवाल उठाती है कि इंसान उन लोगों और मूल्यों की रक्षा के लिए कितना आगे जा सकता है, जिन्हें वह सबसे अधिक चाहता है। फिल्म की कहानी अर्जुन मेहरा (सनी देओल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मशहूर वकील है और अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करता। उसकी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए लड़ते हुए गुजरी है। लेकिन हालात तब बदल जाते हैं, जब उसे शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना) का केस लड़ना पड़ता है। शौर्यमान उसके अतीत से जुड़ा ऐसा शख्स है, जिसका केस वो अपनी मर्जी से कभी नहीं लड़ता। शुरुआत में एक बड़ा कानूनी मामला नजर आने वाली यह लड़ाई जल्द ही अर्जुन के लिए निजी जंग बन जाती है। पुराने जख्म, दबी हुई सच्चाइयां और एक-दूसरे के प्रति वफादारी के बीच टकराव सामने आने लगता है। अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगा होने के कारण, अर्जुन खुद को ऐसी परिस्थितियों में घिरा पाता है, जहां उसके हर फैसले की एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिल्म में दीया मिर्जा अर्जुन की पत्नी अवंतिका और तिलोत्तमा शोम एक दृढ़ निश्चयी सरकारी वकील मधुरा बनर्जी की भूमिका में हैं। मधुरा भी इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कई परतों वाले किरदारों, अदालत में दमदार बहस और जज़्बात से भरे टकराव के जरिए 'इक्का' सिर्फ एक आम कोर्टरूम ड्रामा बनकर नहीं रह जाती, बल्कि मुश्किल फैसलों की इंसानी कीमत को भी सामने लाती है। दमदार अभिनय, दिलचस्प कहानी और जज़्बात से भरे टकराव के साथ 'इक्का' दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव देने का वादा करती है। यह फिल्म कानूनी लड़ाई के रोमांच को रिश्तों, जिम्मेदारियों और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश से जोड़ती है। अर्जुन और शौर्यमान की लड़ाई में दांव सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में दर्शकों के मन में भी यह सवाल उठेगा कि क्या इंसाफ हमेशा उतना ही सीधा होता है, जितना पहली नजर में दिखाई देता है? देखना न भूलें सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर 'इक्का' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, 29 नवंबर को रात 8 बजे, सिर्फ ज़ी सिनेमा पर।

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने सिवान में सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स के नए स्टोर का किया भव्य शुभारंभ

सिवान : भारत के प्रमुख आभूषण रिटेल ब्रांड्स में से एक, सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स, ने आठ दशकों से अधिक की अपनी गौरवशाली विरासत के साथ बिहार में अपने विस्तार को आगे बढ़ाते हुए आज सिवान में अपने नए स्टोर का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। यह स्टोर सेन्को का 100वां फ्रेंचाइज़ी स्टोर भी है। इस नए स्टोर के माध्यम से सिवान और आसपास के क्षेत्रों के ग्राहकों को ब्रांड के सोने और प्राकृतिक हीरों के आभूषणों की विस्तृत रेंज उपलब्ध होगी। भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा पर आधारित इन आभूषणों में पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक डिज़ाइन का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इस स्टोर का शुभारंभ सेन्को के रिटेल नेटवर्क के निरंतर विस्तार के साथ-साथ आभूषण निर्माण की अपनी समृद्ध विरासत, उत्कृष्ट डिज़ाइन और ग्राहकों के विश्वास को नए बाजारों तक पहुंचाने की ब्रांड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आठ दशकों से अधिक समय से ब्रांड ने आभूषणों की विस्तृत रेंज, कुशल कारीगरी और गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा उचित मूल्य निर्धारण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। सिवान स्थित यह नया स्टोर इन्हीं खूबियों को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत करता है, जहां ग्राहकों को शादी-विवाह, त्योहारों, उपहार देने, विशेष अवसरों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आभूषणों की आकर्षक रेंज उपलब्ध होगी। इस भव्य शुभारंभ समारोह में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह शामिल हुईं। उन्होंने नए शोरूम में ग्राहकों और प्रशंसकों से मुलाकात की और इस खास मौके के जश्न में हिस्सा लिया। उनकी मौजूदगी ने सिवान में सेन्को के आगमन को लेकर उत्साह और भी बढ़ा दिया। यह बिहार में अपने रिटेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में ब्रांड का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर रकुल प्रीत सिंह ने कहा, "हर उत्सव और खुशी के मौके पर आभूषणों का एक विशेष महत्व होता है, सेन्को की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि यहां पारंपरिक भारतीय कारीगरी के साथ आज के समय के पसंदीदा और नए डिज़ाइनों का भी खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। यही बात इस ब्रांड को सबसे अलग बनाती है।सेन्को जैसी विरासत वाले ब्रांड के साथ ग्राहकों का गहरा विश्वास भी जुड़ा हुआ है, जो शादी, त्योहार या जीवन के किसी खास व्यक्तिगत अवसर के लिए आभूषण चुनते समय बेहद मायने रखता है।



मुझे सिवान आकर इस नए स्टोर के शुभारंभ का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हो रही है। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि सेन्को अपनी विरासत, उत्कृष्ट कारीगरी और शानदार डिज़ाइनों को यहां के ग्राहकों के और करीब ला रहा है।" इस अवसर पर सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स के डीजीएम (सेल्स) मानस रुद्र ने कहा, "बिहार सेन्को के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इसका प्रमुख कारण यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, आभूषणों के साथ लोगों का गहरा जुड़ाव और सोने एवं उत्कृष्ट कारीगरी के प्रति उनकी विशेष पसंद है। सिवान में हमारे नए स्टोर का शुभारंभ, जो हमारा 100वां फ्रेंचाइज़ी स्टोर भी है, राज्य में हमारी रिटेल उपस्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से ग्राहकों को शादी-विवाह, त्योहारों, उपहार देने और रोजमर्रा के खास मौकों के लिए उपयुक्त डिज़ाइनों की विस्तृत रेंज उपलब्ध होगी।

नई सोच एक्सप्रेस
हर खबर पर पैनी नजर
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

क्राइस्टचर्च टेस्ट : पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन, लैथम और ब्लंडेल के अर्धशतक

एजेंसी, क्राइस्टचर्च

आकाश दीप की शानदार गेंदबाजी के बावजूद टॉम लैथम और टॉम ब्लंडेल के अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 246 रन बना लिए। लैथम ने शीर्ष क्रम में संयमित बल्लेबाजी करते हुए पारी की नींव रखी, जबकि दोपहर के सत्र में भारत के लगातार तीन विकेट लेने के बाद ब्लंडेल ने पारी को संभाला। ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए हुई 62 रन की अटूट साझेदारी दिन की तीन अर्धशतकीय साझेदारियों में से एक रही। उतार-चढ़ाव भरे दिन के अंत में न्यूजीलैंड ने अच्छी स्थिति हासिल कर ली।



भारत के गेंदबाजी चुनने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले घंटे में बिना विकेट गंवाए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज ने गेंद को अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट दिलाई। दोनों ने कई बार बल्लेबाजों के बाहरी किनारे को छकाया। पहले बदलाव के रूप में गेंदबाजी करने आए आकाश दीप ने भी दोनों तरफ मूवमेंट हासिल कर डेवोन कॉनवे को परेशान किया। टॉम लैथम बुमराह की गेंद पर पगबाधा के फैसले से बाल-बाल बचे। उन्होंने समीक्षा ली, जिसमें गेंद ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। भारत ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन लाइन और लेंथ में निरंतरता की कमी के कारण उन्हें विकेट में नहीं बदल सका। आकाश दीप को लैथम का विकेट मिल सकता था, लेकिन दूसरी स्लिप में केएल राहुल ने उनका बाहरी किनारा छोड़ दिया। दूसरी ओर, धीमी शुरुआत के बाद कॉनवे ने नियमित रूप से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू किया और सत्र आगे बढ़ने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी तरह जम चुके थे और बिना विकेट गंवाए लंच तक पहुंचने की स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर पदार्पण कर रहे गुरनूर बराड़ ने कॉनवे को पगबाधा आउट कर दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने फैसले की समीक्षा ली, लेकिन गेंद ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती दिखाई दी। इस तरह न्यूजीलैंड ने 26 ओवर में एक विकेट पर 77 रन बनाकर लंच किया।

लंच के बाद न्यूजीलैंड ने लगातार रन बनाना जारी रखा। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले लैथम ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ने लैथम के खिलाफ संभावित डीआरएस का एक मौका गंवाया। इसके अलावा जोखिम भरे एक रन के लिए दौड़े हेनरी निकोल्स को रन आउट करने का मौका भी हाथ से निकल गया। गेंद में सीम मूवमेंट जारी था और भारतीय गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों को असहज कर रहे थे, लेकिन इन मौकों को विकेट में नहीं बदल सके। न्यूजीलैंड ने लंच के बाद का पहला घंटा बिना कोई विकेट गंवाए निकाल लिया। लंच के बाद दूसरे घंटे में भारतीय गेंदबाजों ने कहीं अधिक आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी की और आकाश दीप ने अगुआई की। दूसरे विकेट के लिए 33 रन जुड़ने के बाद आकाश दीप ने लैथम को विकेट के पीछे कैच कराकर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद कंबोज ने निकोल्स को आउट किया, जो पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे। बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने फिर रचिन रवींद्र को भी विकेट के पीछे कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। एक विकेट पर 110 रन से न्यूजीलैंड का स्कोर चार विकेट पर 110 रन हो गया। डैरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल ने सत्र का बाकी खेल संभाला। न्यूजीलैंड ने इस सत्र में 24 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 54 रन बनाए। इस दौरान मिचेल पगबाधा की अपील पर भी बच गए और भारत ने एक समीक्षा गंवा दी।

क्राइस्टचर्च टेस्ट-लंच के बाद सही लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करने का मिला फायदा : आकाश दीप

एजेंसी, क्राइस्टचर्च

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दो विकेट लेकर भारतीय टीम को वापसी दिलाने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप ने कहा कि दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच के बाद अनुशासन और धैर्य के साथ गेंदबाजी करने से भारतीय टीम को वापसी करने में मदद मिली। हालांकि, मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 110 रन से वापसी करते हुए दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 246 रन बना लिए। आखिरी सत्र में टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने 62 रन की अटूट साझेदारी कर न्यूजीलैंड को संभाला।



सुबह नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिली, लेकिन टीम इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकी। कई बार गेंद का बाहरी किनारा लगा, लेकिन वह क्षेत्ररक्षकों तक नहीं पहुंचा। दो विकेट लेने वाले आकाश दीप ने माना कि भारत पहले दिन इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। हालांकि, उन्होंने कहा कि लंच के बाद विकेट लेने की जल्दबाजी करने के बजाय सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने पर ध्यान देने की रणनीति सफल रही। आकाश दीप ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "पहले सत्र में गेंद में कुछ नमी थी और वह ज्यादा तेजी से बल्ले पर नहीं आ रही थी। इसलिए किनारे से लगकर निकलने वाली गेंदें क्षेत्ररक्षकों तक नहीं पहुंच रही थीं। शुरुआत में हम गेंद को कुछ ज्यादा ही स्विंग करा रहे थे। लंच के बाद हमने सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने और धैर्य बनाए रखने पर ध्यान देने का फैसला किया। यही हमारी योजना थी और इससे हमें तीन विकेट हासिल करने में मदद मिली। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहा, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते थे। हालांकि, कोई बात नहीं।" आकाश दीप ने बताया कि उनका व्यक्तिगत ध्यान बल्लेबाजों को अधिक से अधिक गेंद खेलने के लिए मजबूर करने पर था। खासकर पहले दिन परिस्थितियां गेंदबाजों के अनुकूल थीं। उन्होंने कहा, "हमें पता था कि यह पहला दिन है और गेंदबाजों को मदद मिल रही है। इसलिए हम इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते थे। मेरा ध्यान बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने के लिए मजबूर करने पर था। मैंने अपने पहले स्पेल में पांच या छह ओवर गेंदबाजी की और कोशिश की कि बल्लेबाज 80 से 90 प्रतिशत गेंदों पर शॉट खेलने के लिए मजबूर हो। एक तेज गेंदबाज के लिए इस तरह की निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी आप स्टंप पर गेंद डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी लाइन थोड़ी भटक सकती है।" आकाश दीप का मानना है कि गेंद पुरानी होने के साथ बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती गईं। ऐसे में गेंदबाजों के सामने रन रोकने के साथ विकेट लेने की कोशिश जारी रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है और हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाती है।

जोदार के दम पर स्पेन डेविस कप के सेमीफाइनल में, ब्रिटेन से होगा मुकाबला

एजेंसी, बोलोग्ना

राफेल जोदार ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए स्पेन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत दिलाई। इस जीत के साथ स्पेन ने डेविस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां गुरुवार को उसका मुकाबला ब्रिटेन से होगा। बोलोग्ना में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना रखी थी। इसके बाद जोदार को ऑस्ट्रिया के यूरी रोडियोनोव के खिलाफ पहला सेट गंवाना पड़ा लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले दो सेट में केवल एक गेम गंवाया और 2-6, 6-0, 6-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल भी जीत लिया। 20 वर्षीय जोदार ने मैच के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा, "मेरे लिए यह मुकाबला काफी मुश्किल था क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में शुरुआती मैच आसान नहीं होते। मैं अपनी लय हासिल नहीं कर पा रहा था। दूसरे सेट की शुरुआत में मैंने बेहतर, अधिक आक्रामक और बेसलाइन से अधिक मजबूत खेलना शुरू किया। मुझे लगता है कि इसी से मुझे मुकाबले में वापसी करने में मदद मिली।" इससे पहले डेनियल मेरिडा ने जोएल श्वार्जलर को 6-4, 6-4 से हराकर स्पेन को पहली जीत दिलाई थी। इस तरह मुकाबले में युगल मैच की जरूरत नहीं पड़ी और कार्लोस अल्कराज को आराम मिल गया। मेरिडा ने कहा, "स्पेन को पहला अंक दिलाना मेरे लिए शानदार अनुभव था। मुझे लगता है कि यहां हमारी टीम अच्छी है। आज मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं खेल पाया लेकिन जीत हासिल करने में सफल रहा।" स्पेन के कप्तान डेविड फेरर ने कहा कि लगातार तीन व्यक्तिगत खिताब जीत चुके अल्कराज शनिवार को ब्रिटेन के खिलाफ एकल मुकाबले में उतर सकते हैं। इनमें पिछले सप्ताह जीता गया एटीपी फाइनल्स का खिताब भी शामिल है। सात बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अल्कराज के खेलने की संभावना पर फेरर ने कहा, "मैं शनिवार को देखूंगा। अभी मुझे नहीं पता है लेकिन हां, ऐसा संभव हो सकता है।" स्पेन की टीम सातवीं बार डेविस कप खिताब जीतने के इरादे से उतरी है। हालांकि, उसने आखिरी बार 2019 में यह खिताब जीता था, तब राफेल नडाल ने टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी।



काहिरा में 09 दिसंबर से होगा पहला एफआईएच यूथ हॉकी5एस विश्वकप, भारत की पुरुष और महिला टीमें लेंगी हिस्सा

एजेंसी, नई दिल्ली

पहले एफआईएच यूथ हॉकी 5 ए साइड विश्वकप 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में 09 से 12 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमें दुनिया की उभरती युवा हॉकी प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत ने इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता के लिए इसी साल जुलाई में ओमान के मस्कट में आयोजित यूथ हॉकी 5 ए साइड एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के दम पर क्वालीफाई किया था। भारतीय युवा पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर विश्वकप में अपनी जगह पक्की की थी, जबकि महिला टीम ने रजत पदक हासिल कर विश्वकप के लिए क्वालीफाई किया था। इस तरह भारत दोनों वर्गों में अपनी चुनौती पेश करेगा। पुरुष वर्ग में भारत को पूल बी में बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और चिली के साथ रखा गया है। भारतीय युवा टीम महाद्वीपीय प्रतियोगिता में मिली सफलता की लय को बरकरार रखते हुए विश्वकप के पहले संस्करण में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। वहीं, भारतीय महिला टीम पूल ए में मेजबान मिस्र, ब्राजील और कजाखस्तान के साथ है। मस्कट में रजत पदक जीतकर विश्वकप में जगह बनाने वाली भारतीय महिला टीम वैश्विक मंच पर अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने तथा खिताब की दौड़ में शामिल होने के इरादे से उतरेगी। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की उभरती हॉकी प्रतिभाएं हिस्सा लेंगी। युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने और तेज गति वाले हॉकी पांच प्रारूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल 11 दिसंबर को खेले जाएंगे, जबकि पदक मुकाबले 12 दिसंबर को होंगे। इसी दिन काहिरा में पहले यूथ पुरुष और यूथ महिला हॉकी 5 ए साइड विश्व चैंपियन का फैसला होगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने दोनों टीमों पर भरोसा जताते हुए प्रतियोगिता से पहले उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "पहले एफआईएच यूथ हॉकी 5 ए साइड विश्व कप में खेलना हमारी दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।



बिजनेस

भारतीय निर्यातकों से अधिक भागीदार देश उठा रहे एफटीए का लाभः आरबीआई गवर्नर

एजेंसी, नई दिल्ली/मुंबई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने वाले देश इन समझौतों का लाभ भारतीय निर्यातकों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों से इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एसएमई वित्त और निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस शिखर सम्मेलन में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण, विस्तार तथा नवाचार पर जोर दिया है। मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू निर्यातक एफटीए का 'बहुत कम' इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत कम शुल्क का लाभ उठाने के



पात्र भारतीय निर्यातकों में से केवल 20-30 फीसदी ही इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई एक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक हैं। मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू निर्यातक एफटीए का 'बहुत कम' इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत कम शुल्क का लाभ उठाने के पात्र भारतीय निर्यातकों में से केवल 20-30 प्रतिशत ही इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''भारत को निर्यात करने वाले भागीदार देशों के 60-70 फीसदी निर्यातक इन समझौतों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारत में इनका इस्तेमाल बेहद कम है। इस तरह हम एक बड़े अवसर का लाभ उठाने से चूक रहे हैं।'' आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कारोबारियों से मिलना महत्वपूर्ण है और उनकी मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिजर्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने इस क्षेत्र को किसी भी अर्थव्यवस्था की 'जीवनरेखा' बताया। उन्होंने बैंकों से एमएसएमई क्षेत्र को कर्ज देने को केवल नियामकीय अनुपालन का मामला नहीं मानने को कहा। बैंकों को इन उद्यमों को अपनी वृद्धि में संभावित भागीदार के रूप में देखना चाहिए और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के सामाजिक महत्व को भी समझना चाहिए। मल्होत्रा ने कहा, 'भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 31 फीसदी है।

विनिर्माण उत्पादन में इसका योगदान 35 फीसदी और वस्तुओं के कुल निर्यात में करीब आधा है। कृषि के बाद यह रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और 45 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।' संजय मल्होत्रा ने एमएसएमई ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग खारिज कर दी। उन्होंने छोटे कारोबारियों से ऋणदाताओं के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत करने और अपनी नकदी की उपलब्धता के अनुरूप ऋण चुकाने के लिए अधिक मोहलत लेने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि उनका ऋण एनपीए बनने से बच सके। एसएमई वित्त और निवेश शिखर सम्मेलन के इस संबोधन में संजय मलहोंत्रा ने भारत की विकास यात्रा में एमएसएमई की भूमिका, वित्त तक पहुंच बेहतर बनाने के उपायों और इस बात पर चर्चा किया कि कैसे उद्यम और ऋणदाता मिलकर उत्पादकता, नवाचार और विस्तार (स्केल) को बढ़ावा दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले पांच वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इनमें से कुछ समझौते अभी लागू होने बाकी हैं, जबकि अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है।

सोने का भाव 25 दिन में 17,000 टूटा

एजेंसी, नई दिल्ली । नवंबर महीना सोने के निवेशकों और खरीदारों के लिए एक बड़े झटके या सुनहरे अवसर दोनों की तरह सामने आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर पिछले 25 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 12 फीसदी से अधिक है। वहीं, अपने जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से यह 31 फीसदी टूटकर 55,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को 1,38,485 रुपए पर बंद हुआ सोना 26 नवंबर को 1,21,478 रुपए तक गिर गया था। यानी महज 25 कारोबारी दिनों में इसकी कीमत में 17,000 रुपए से अधिक की गिरावट आई। 25 नवंबर को तो यह 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भी नीचे चला गया था, जो इस गिरावट के चरम को दर्शाता है। हालांकि, शुक्रवार को बाजार में रौनक लौटी और सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। खबर लिखे जाने तक, सोना 2,973 की बढ़त के साथ 1,25,245 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 8,339 रुपए उछलकर 1,54,182 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पूरा होने के करीबः पीयूष गोयल

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरा होने के करीब है। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब आकार ले रही है। गोयल ने वर्चुअल माध्यम से 'इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट 2026' को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ''अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरा होने के करीब है। वह प्रक्रिया और मार्ग, जिसकी वजह से समझौते को अंतिम रूप देने में हमेशा रुकावट आती थी, उसमें अब कुछ बात बन रही है।' केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पूरा होने के करीब है। गोयल ने कहा कि इस समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तथा रूपरेखा अब आकार ले रही है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ना जारी रखा है। सुधार लागू किए हैं और आर्थिक नींव को



मजबूत किया है। साथ ही वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर विकास के व्यापक अवसर भी प्रदान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर इस वर्ष के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि यह अगले वर्ष मार्च या अप्रैल तक लागू हो सकता है। उन्होंने कहा, "आर्थिक आंकड़े इन प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं।" गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम विनिर्माण क्षेत्र में कथित "संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता" से जुड़ी जांच के बाद उठाया है। हालांकि भारत सरकार ने साफ तौर पर इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में ऐसी अतिरिक्त क्षमता मौजूद नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने डेट कैपिटल मार्केट समिट की थीम 'कैटेलिस्ट्स, कैपेक्स एंड क्रेडिट' की भी तारीफ की और कहा कि भारत की विकास कहानी में पूंजी, निवेश और विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड मार्केट, क्रेडिट मार्केट और पूंजी बाजार मूल रूप से निवेशकों के भरोसे पर आधारित होते हैं और यही भरोसा भारत की आर्थिक प्रगति को गति देता है।

लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 165 अंकों की गिरावट

एजेंसी, नई दिल्ली

हफ्ते के पाचवें एवं अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 165 अंकों और निफ्टी में 49 अंकों की गिरावट दर्ज की गई । बाजार में शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 146.64 अंक यानी 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 84,181.95 अंक के स्तर पर ट्रेंड करता नजर आया।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 38.95 अंक यानी 0.15 फीसदी गिरकर 25,845.55 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और बीईएल जैसे प्रमुख शेयरों में एक फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अधिकतर क्षेत्रीय सूचकांकों में तेजी देखी गई। लेकिन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट, रियल्टी, रसायन, वित्तीय सेवाओं और एफएमसीजी शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा आज मेटला शेयर्स में ज्यादा खरीदारी है। वहीं आईटी में बिकवाली देखने को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.31 अंकों यानी 0.46 फीसदी उछलकर 84,328.59 अंकों पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 65.25 अंक यानी 0.25 फीसदी बढ़कर 25,884.50 के स्तर पर बंद हुआ था।

अगले दो दशकों में बिजली क्षेत्र में 200 लाख करोड़ रुपये निवेश का मौका : मनोहर लाल

एजेंसी, नई दिल्ली । केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में अगले दो दशकों में 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दो दिवसीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकें। विद्युत मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विद्युत नियामक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। इससे पहले यह सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन भारत के विद्युत क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं और उनके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श का मंच है।



केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत 13 क्षेत्रों के 200 से अधिक हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकें पूर्ण

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 क्षेत्रों के 200 से अधिक हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकें पूरी कर ली हैं। बजट पूर्व बैठकों में कई महत्पपूर्ण सुझावों पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए तैयारियों के तहत व्यापक पूर्व-बजट परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन पूर्व-बजट परामर्शों में 13 क्षेत्रों और हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि इन बैठकों के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट कृत्रिम मेधा (एआई) मॉडलों के विकास, किफायती आवास के लिए किराये के मकानों को बढ़ावा देने व रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर पैदा करने के लिए मझोले एवं छोटे शहरों के विकास में तेजी लाने सहित कई सुझाव दिए गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बजट पूर्व बैठक में हितधारकों ने जैव उर्वरकों और जैव प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत कृषि सामग्रियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाए।



स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आरती कुमारी द्वारा अभिषेक प्रिंटिंग प्रेस, नया टोला, काजीपुर, पटना- 800004, से मुद्रित एवं मुसल्लहपुर हाट, रामपुर लेन, पटना 800006 से प्रकाशित। संपादक- अविनाश। संपादकीय कार्यालय : 8 वां तल्ला, रश्मि कॉम्प्लेक्स, पीएनटी कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना- 800001, RNI: BIHHIN\2019/77032, फोनः 0612-2524441, 2951617, 9472072441, 9472244606, समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेवार।